सोशल मीडिया से जुड़ें
NewsTransportVishesh

Digital Edition

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 1, अंक 70, नई दिल्ली, शनिवार, 07 जनवरी 2023, पेज 8

NEWS TRANSPORT VISHESH NTV
www.newstransportvishesh.com
सबसे तेज, सबसे पहले
आपको पहुंचाये परिवहन क्षेत्र की सभी जानकारियां
09212122095
09811732095

03 एमसीडी मेयर इलेक्शन: हंगामा क्यों बरपा? आप को किस बात का डर
05 सीएनजी के साथ आई मारुति की पावरफुल एसयूवी
08 रूस हो या यूक्रेन भारत को लेकर क्यों आलोचनात्मक नहीं होते

आज का सुविचार

छोटी चीजों में बारे हमेशा वफादार रहिये क्योंकि इन्ही में आपकी शक्ति निहित होती है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में भ्रष्टाचार नहीं, मैं ठेकेदारों से नहीं मिलता : नितिन गडकरी

उन्होंने कहा कि 17 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली नई ग्रीनफील्ड परियोजना बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे मार्च 2024 तक पूरी हो जाएगी।

संजय बाटला

बेंगलुरु। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि उनके मंत्रालय में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की लागत में वृद्धि की गुंजाइश लगभग शून्य हो चुकी है। हर साल हम पांच लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम करते हैं। अब तक मैंने 50 लाख करोड़ रुपये के काम किए हैं। मैं ठेकेदारों से नहीं मिलता। हमारे मंत्रालय में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है।

उन्होंने बेंगलुरू-मैसूर राजमार्ग कार्य का निरीक्षण करने के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम गुणवत्ता को लेकर सख्त हैं। अगर आपको काम की गुणवत्ता को लेकर संदेह है तो कृपया मुझे बताएं। इससे पहले उन्होंने कहा कि 17 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली नई ग्रीनफील्ड परियोजना बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे मार्च 2024 तक पूरी हो जाएगी। गडकरी ने बेंगलुरु के बाहरी इलाके में होसकोटे के पास वडगनहल्ली में परियोजना का निरीक्षण करने के बाद कहा कि 285.3 किलोमीटर की इस चार लेन परियोजना से यात्रा समय की बचत होगी। इससे प्रमुख शहरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से गुजरने में होने वाली देरी से बचने में भी मदद मिलेगी। गडकरी ने कहा कि कर्नाटक में 71.7 किलोमीटर की इस भारतमाला परियोजना पर 5,069 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 231 किलोमीटर पर निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है। मार्च, 2024 तक हम इस परियोजना को पूरा करना चाहते हैं। गडकरी ने कहा कि बेंगलुरु-मैसूरु राजमार्ग परियोजना फरवरी 2023 तक पूरी हो जाएगी। हम इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने राजमार्गों का हवाई सर्वेक्षण भी किया।

इनसाइड

सीएम गुरुग्राम से करीब 15 करोड़ की विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन एवं शिलान्यास

गुरुग्राम. मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला को करीब 15 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुक्रवार को सौगात देंगे। गुरुग्राम से वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसमें जिले से संबंधित 9.32 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का उद्घाटन होगा तथा 6.24 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। शहर के एसडीएम कॉम्प्लेक्स में स्थित एनआईसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हाल में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। डीसी डॉ प्रियंका सोनी ने समारोह की तैयारियों के संबंध में बैठक कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रातः 11 बजे से आरंभ होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्चुअल माध्यम से अंबाला जिला की दो योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा द्वारा शहजादपुर में 34.78 लाख की लागत से बनाया गया राजकीय पशु चिकित्सालय और गांव बड़ागढ़ में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा 898.00 लाख की लागत से बनाया गया मॉडर्न स्पोर्टस स्टेडियम शामिल है।

खटीमा बाईपास बनाने का सपना आज पूरा हो गया: धामी

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खटीमा बाईपास का श्रेय जनता का है। यहां की जनता ने उन्हें 2012 में विधायक चुना। तब से ही खटीमा बाईपास बनाने का सपना था। यह आज पूरा हो गया।

विधायक बनने पर बाईपास का मसौदा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के प्रयास से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पहुंचा। तब बाईपास के लिए 25 करोड़ मिले। इससे सितारगंज रोड से नगर के मुख्य चौराहे से टनकपुर रोड निर्माण एनएचएआई की ओर से किया गया। हालांकि बाईपास निर्माण की योजना तब थारू और गैर थारू भूमि विवाद के चलते परवान नहीं चढ़ सकी। इसके लिए फिर से प्रस्ताव भेजा गया था।

उन्होंने कहा कि बाईपास निर्माण कार्य में कौमी एकता की मिशाल कायम हुई। आपसी रजाबंदी से मूल काश्तकार व कब्जेदारों में सहमति बनी और भूमि का एनएच को हस्तांतरण हुआ। सीएम धामी ने कहा कि इस कार्य में शासन-प्रशासन और जन प्रतिनिधियों का पूरा योगदान रहा। वर्ष 2012 से बाईपास का सपना 2022-23 में पूरा हो सका।

उन्होंने भारामल बाबा मंदिर के सौंदर्यीकरण, नागरिक अस्पताल, शारदा में घाट निर्माण, एकलव्य विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, रोडवेज स्टेशन आदि विकास कार्यों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

पूर्व सैनिकों ने सौंपा ज्ञापन

पूर्व सैनिक संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर खटीमा में सैनिक मिलन केंद्र निर्माण के लिए धन अवमुक्त कराने की मांग की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को सौंपे गए ज्ञापन में एक्सटेंडेट सीएसडी कैंटीन के पूर्ण कैंटीन का दर्जा दिलाने की मांग की है। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन गंभीर सिंह धामी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व सैनिक संगठन जिलाध्यक्ष सूबेदार मेजर खड़क सिंह कार्की, कैप्टन ठाकुर सिंह खाती, राजेंद्र अधिकारी, होशियार सिंह बोहरा, दान सिंह बोहरा, धर्म सिंह बिष्ट आदि थे। संवाद

> यह 94.58 करोड़ की लागत से 8.225 किमी लंबा टूलेन विद पेव्ड शोल्डर बाईपास है। इससे बनबसा, टनकपुर, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट व धारचूला के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

धामी ने खटीमा के प्रति अपना स्नेह, प्रेम नहीं छोड़ा: भट्ट

केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के प्रति अपना स्नेह, प्रेम नहीं छोड़ा। वह हर बार खटीमा आते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। पीएम मोदी तीसरी बार रेटिंग में भी नंबर एक पर आए हैं। वह कभी किसी के खिलाफ नहीं बोले। यह भी कहा कि नेपाल मेरी ससुराल है। रोटी-बेटी का रिश्ता है। नेपाल को भारत से जोड़ने के लिए सड़क स्वीकृत हो गई है जिसका नेपाल की ओर से काम शुरू हो गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1100 करोड़ रुपये ऊधमसिंह नगर जिले के लिए और एक हजार करोड़ रुपये नैनीताल जिले के लिए दिए गए हैं। संवाद

गदरपुर बाईपास

काशीपुर से रुद्रपुर के बीच स्थित यह बाईपास 170 करोड़ रुपयों की लागत से बना है। इसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर है। यह चार लेन का यह रास्ता है। अब गदरपुर शहरी क्षेत्र में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। काशीपुर से रुद्रपुर और सितारगंज की यात्रा सुगम होगी।

खटीमा बाईपास

यह 94.58 करोड़ की लागत से 8.225 किमी लंबा टूलेन विद पेव्ड शोल्डर बाईपास है। इससे बनबसा, टनकपुर, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट व धारचूला के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली, देहरादून व हरिद्वार को जाने वाले लोग अब कम समय में सफर तय कर सकेंगे।

खटीमा बाइपास निर्माण कार्य सबसे कठिन था। इस कार्य में सीएम का भरपूर सहयोग मिला। अलग से रिवाई करवाया और सीएम तथा प्रशासन ने सभी कठिनाइयों का समाधान कराया। दोनों बाइपास निर्माण कार्य को पूरा कर जनता को समर्पित किया जा रहा है।

-सीके सिन्हा, रीजनल ऑफिसर, एनएचएआई

रैपिड रेल स्टेशनों से 17 रूटों पर चलेंगी फीडर बसें, जानें इनके रूट

एनटीवी संवाददाता

नयी दिल्ली. मेट्रो की तर्ज पर देश की पहली रैपिड रेल के यात्रियों की सुविधा के लिए आरआरटीएस फीडर बस चलाने की तैयारी कर रहा है. आरआरटीएस के स्टेशनों से करीब 17 रूटों पर फीडर बसें चलेंगी. इसके लिए आरआरटीएस की ओर से आरटीओ में परमिट के लिए आवेदन किए गए हैं. इस संबंध में 10 जनवरी को आरटीओ और आरआरटीएस के अधिकारियों के साथ बैठक है, जिसके बाद फैसला किया जाएगा. जानकारी के अनुसार बैठक में ही फैसला होगा कि प्रति स्टेशन को जोड़ने के लिए कितनी फीडर बसों के लिए आरटीओ विभाग की ओर से परमिट जारी किए जाएंगे. आरआरटीएस का सबसे पहले करीब 18 किलोमीटर लंबा रूट शुरू होगा.

आरआरटीएस की योजना के अनुसार रैपिड रेल दौड़ने के साथ ही यात्रियों को फीडर बस सेवा शुरू कर दी जाए.

आरआरटीएस दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर यह सुविधा देने की तैयारी में है. इसके लिए आरआरटीएस का अपना अलग से ट्रांसपोर्ट विभाग होगा. आरआरटीएस की ओर से प्लान किया गया है कि तीन स्टेशनों साहिबाबाद, गाजियाबाद और गुलधर स्टेशनों यात्रियों को फीडर बसों की सुविधा मिल सके.

फीडर बसों की सुविधा के लिए आरआरटीएस का पूरा फोकस इस बात पर है कि अधिक से अधिक परमिट प्रशासन से मिलें, जिससे रैपिड रेल यात्री आसानी से अपने गंतव्य पर पहुंच सकें.

ये होंगे संभावित रूट

साहिबाबाद स्टेशन से

1-लोनी-शालीमार गार्डन, साहिबाबाद रेलवे स्टेशन
2- हिंडन एयरपोर्ट-शालीमार गार्डन-साहिबाबाद रेलवे स्टेशन
3- लोनी-मोहन नगर
4- हिंडन एयरपोर्ट- मोहन नगरर
5-नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन-सीआईएसएफ रोड-इंदिरापुरम-वसुंधरा
6-नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन-आदित्य माल- इंदिरापुरम-वसुंधरा
7- यूपी गेट-डाबर चौक-वैशाली मेट्रो स्टेशन-साहिबाबाद मंडी
8- यूपी गेट-अभयखंड-ज्ञानखंड-बड़ा चौक-अटल चौक –वसुंधरा
9-कौशांबी बस स्टैंड- साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र

गाजियाबाद स्टेशन से

1-नोएडा सेक्टर 51-52- गौड़ चौक- प्रताप विहार- सिद्धार्थ विहार
2- गौड़ चौक- क्रासिंग रिपब्लिक- विजय नगर – सिद्धार्थ विहार
3- लालकुआं-नेहरू नगर- सदर तहसील-पुराना बस अड्डा- नया आर्य नगर
4-लालकुआं-लोहा मंडी-लोहिया नगर-नवयुग मार्केट

गुलधर स्टेशन से

1-वेबसिटी मनिपाल हास्टिपल-एएलटी सेंटर
2- डासना-गंगापुरम-एएलटी सेंटर
3- गाजियाबाद रेलवे स्टेशन

कानपुर चारों तरफ से नेशनल हाइवे से घिरा है। ऐसे में यातायात नियमों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है

सड़क सुरक्षा जागरूकता को जनांदोलन बनाएं, 4 फरवरी तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा माह

एनटीवी संवाददाता

कानपुर। डीएम ने कहा कि पांच जनवरी से चार फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी का जीवन अनमोल है। इसलिए वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें।

कानपुर में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। सिर्फ सड़क सुरक्षा सप्ताह और माह मनाना ही पर्याप्त नहीं है। सड़क सुरक्षा जागरूकता को जनांदोलन बनाने की जरूरत है।

यह बात जिलाधिकारी विशाख जी ने विकासनगर में रोडवेज के ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सड़क सुरक्षा माह के उद्घाटन के मौके पर कही। उन्होंने बताया कि सुरक्षित, सुगम यातायात और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पांच जनवरी से चार फरवरी तक यह मनाया जाएगा।

डीएम ने कहा कि कानपुर चारों तरफ से नेशनल हाइवे से घिरा है। ऐसे में यातायात नियमों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। सीट बेल्ट, हेलमेट का इस्तेमाल, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने और नशे की हालत में वाहन न चलाने की सीख दी।

उन्होंने इसे जनांदोलन बनाने के लिए सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी, एनसीसी के कैडेटों, ई रिक्शा चालकों, ऑटो चालकों, परिवहन निगम में प्रशिक्षण ले रहे चालकों को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। आरटीओ प्रशासन राजेश सिंह ने महीने भर चलने वाले जागरूकता कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी।

प्रचार वाहन को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीटीसी विजय कुमार, एआरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा, एआरटीओ प्रवर्तन उदयवीर सिंह ,सुनील दत्त, अंबुज और मानवेंद्र सिंह, बीएसए सुरजीत सिंह, पुलिस उपायुक्त यातायात तेज स्वरूप सिंह मौजूद रहे।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

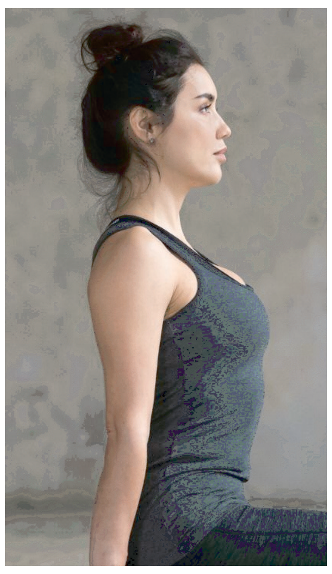

महिलाएं हर दिन करें ये 3 योगासन, बिना जिम के मिलेगा स्लिम-ट्रिम लुक

एक्सरसाइज या योग करना सेहत के लिए फायदेमंद है. नियमित योग और एक्सरसाइज करने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है. इससे कई बीमारियों से निजात भी मिलती है. बिजी रहने की वजह से या घर से बाहर न जाने की आदत के चलते कई बार महिलाओं के लिए जिम या योग केंद्र जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. कई बार महिलाएं चाहते हुए भी जिम नहीं जा पाती हैं और अपनी सेहत के साथ समझौता कर लेती हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो घर में रहकर भी कुछ खास योगासन की मदद ले सकती हैं. जो आपको स्वस्थ रखने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं.

यूपी के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट की क्लीनिकल योग इंस्ट्रक्टर डॉ. वंदना अवस्थी से उन योगासनों के बारे में जानते हैं, जो आपको स्वस्थ रखने के साथ कई बीमारियों से राहत देने में मदद करेंगे. वैसे तो कोई भी आसन सुबह के समय करना बेहतर होता है लेकिन समय न मिलने पर जब भी करें तो खाना खाने के बाद कम से कम दो घंटे का गैप जरूर रखें. इतना ही नहीं इन योगासनों को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

चक्की चलनासन

इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट बिछाकर बैठ जायें. अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर मैक्सिमम गैप बनाएं. इस दौरान रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे. अब हाथों को जमीन पर एकदम सामने की ओर सीधा रखकर उंगलियों को आपस में फंसा लें. फिर अपने हाथों को क्लॉक वाइज यानी दायीं से बायीं तरह गोल-गोल उसी तरह से घुमायें जैसे चक्की चलाई जाती है. इसके बाद विपरीत दिशा में यही प्रक्रिया दोहराएं. इस योगासन को शुरू में एक-दो मिनट करें फिर धीरे-धीरे समय को बढ़ाएं. इस योगासन से पीसीओडी की दिक्कत में राहत मिलती है. जिससे अनियमित मासिक धर्म धीरे-धीरे नियमित होने लगता है साथ ही दर्द और ऐंठन से भी राहत मिलती है. इतना ही नहीं ये मेंटल स्ट्रेस को कम करने और मोटापे से निजात दिलाने में भी मदद करता है.

तितली आसन

तितली आसन करने के लिए योगा मैट पर सूर्य की ओर मुख कर के आराम की मुद्रा में बैठें. फिर अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर इस तरह से मोड़ें जिससे दोनों पैरों के तलवे आपस में मिल जायें. अब दोनों हाथों से पैर के तलवों को अच्छी तरह से पकड़ लें.अब तितली की तरह अपने पैरों को हिलाएं. इस आसन को भी शुरू में एक-दो मिनट करें फिर अपनी कैपिसिटी के अनुसार धीरे-धीरे इसका समय बढ़ाएं. तितली आसन करने से भी पीसीओडी की दिक्कत से राहत मिलती है. साथ ही पीठ का दर्द और मसल्स स्ट्रेस भी दूर होता है. इतना ही नहीं इस आसन को तीन महीने की गर्भावस्था के बाद भी किया जा सकता है. ये आसन डिलीवरी को आसान बनाने में भी मदद करता है. नियमित रूप से तितली आसन करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.

दंडासन

दंडासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर बैठ जायें और पैरों को सामने की ओर फैला कर आपस में मिला लें. फिर दोनों हाथों को कंधों के बराबर अपनी जांघों के पास सीधा जमीन पर रखें.इस बीच रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें. अब दोनों पैरों के पंजो को अपनी ओर खींचें, कुछ सेकेंड रोक कर रखें फिर ढीला छोड़ दें. इस प्रक्रिया को दस से पंद्रह बार अपने सामर्थ्य के अनुसार दोहराएं. इस आसन को किसी भी आयु और अवस्था की महिलाएं आसानी से कर सकती हैं. दंडासन करने से कंधों में खिंचाव की दिक्कत कम होती है. रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होती है, मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और पाचन शक्ति बढ़ती है।

दोस्तों अगर देते हैं इन चार बातों की सलाह तो भूलकर भी ना करें ऐसा वरना उठानी पड़ सकती है परेशानी

किसी के कहने पर दवाओं का सेवन करना हानिकारक हो सकता है. आजकल जिसे देखो वह दूसरों को बात-बात में सलाह देता रहता है. इनमें से कुछ एडवाइस काम की होती हैं और कुछ को ना मानना ही ठीक होता है. यदि आपकी भी सहेलियां, रिश्तेदार या फिर ऑफिस कलीग वजन घटाने, वर्कआउट करने, डाइटिंग करने या फिर मेकअप, पहनावे से लेकर रिलेशनशिप, करियर आदि पर सलाह देते हैं तो सुन जरूर लें, लेकिन फॉलो वही करें जो आपको अपने लिए सही और बेस्ट लगता हो. अक्सर दोस्त अपना समझकर नसीहत देते हैं, लेकिन उन्हें आंख मूंदकर मानने से बचना चाहिए. मित्रवत सलाह आमौतर पर लोग अपने अनुभवों और आपके प्रति चिंतित होकर देते हैं. ऐसे में जरूरी नहीं कि उन्हें जो चीज सूट करती हो, फायदेमंद साबित हुई हो, वह आपके लिए भी सही ही हो. खासकर, जब सलाह सेहत से संबंधित दी जा रही हो. न्यूवूमनइंडिया डॉट कॉममें छपी एक खबर के अनुसार, शारीरिक और साइकोलॉजिकल हेल्थ एडवाइस आप सिर्फ विशेषज्ञों या डॉक्टर की राय पर ही फॉलो करें. बेशक, आप अपनी दोस्त को अच्छी तरह से जानती-समझती हों, आप दोनों की दोस्ती कितनी भी अच्छी क्यों न हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लिए बिना किसी भी तरह की दोस्ताना सलाह लेने में नासमझी न करें. हम आपको यहां 4 फ्रेंडली एडवाइस के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें कभी भी आंख मूंदकर नहीं फॉलो करना चाहिए.

वर्कआउट

अक्सर जो लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं, वह सामने वाले को भी वही करने की सलाह देते हैं, जो वे खुद डेली रूटीन में करते हैं. यदि आपकी कोई दोस्त फिटनेस फ्रीक है और आपको वर्कआउट से संबंधित एडवाइस दे तो उसे सिर्फ जानकारी के तौर पर सुनें. आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, यह आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता. वर्कआउट करने से पहले आपको मेडिकल हिस्ट्री, परिवार में चली आ रही है बीमारियां, आपकी मेडिकल कंडीशन पर विचार करके ही वर्कआउट करने की योजना बनाएं. आप इसके लिए किसी फिटनेस एक्सपर्ट और ट्रेनर की सलाह जरूर ले लें.

खानपान की आदत

आपका जैसा खानपान होगा उसी अनुसार आपकी सेहत भी बनेगी. आप अपनी फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखकर ही अपना फूड इनटेक करें. आप दूसरों की सलाह पर अपनी डाइट तय ना करें. आपकी दोस्त कोई डाइट फॉलो कर रही है तो उसके कहने पर आप भी उन चीजों का सेवन ना करें. शरीर में विभिन्न हार्मोनल फंक्शन, पाचन एंजाइम्स के कार्यों, पोषक तत्वों की जरूरत और अधिकता के साथ-साथ आपके रक्त में कुछ घटकों के स्तर को समझने के बाद ही उचित डाइट किसी के लिए तय की जाती है. ऐसे में सिर्फ दोस्त के कहने पर कोई भी डाइट फॉलो करना सही नहीं है.

दवाओं का सेवन

फ्रेंड सर्किल में कोई ना कोई ऐसा होता है, जो हर कॉमन बीमारी के लिए दवा लेने की सलाह जरूर दे देगा. ये दवाएं निश्चित रूप से आपको आराम पहुंचा सकती हैं, लेकिन ये आपके शरीर के अनुकूल नहीं हुईं तो इनके कुछ साइड एफेक्ट्स भी हो सकते हैं. यह आपके महत्वपूर्ण अंगों को भी स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए केवल उन्हीं दवाओं का सेवन करें, जो आपको डॉक्टर ने सलाह दी हो.

करियर और रिश्तों पर सलाह

जब आपके करियर और रिश्तों से जुड़े मुद्दों की बात आती है तो इसका फैसला आप खुद लें ना कि किसी के कहने पर आप अपने करियर और लाइफ पार्टनर का चुनाव करें. हर किसी की राय जानें, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ही उसका चुनाव करें. यदि आपकी दोस्त डॉक्टर बनना चाहती है तो आप भी वही करें, ये जरूरी नहीं है. सुनें सभी की, लेकिन करें अपने मन और इच्छानुसार. रिश्तों में भी वही बात शामिल है. यदि आपको कोई पसंद नहीं तो अपने दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर उससे किसी भी तरह के रिलेशन में ना बंधें.

कुछ सामान्य लक्षण जो 5 तरह के गाइनेकोलॉजिकल कैंसर में होते हैं कॉमन, आप भी दें ध्यान

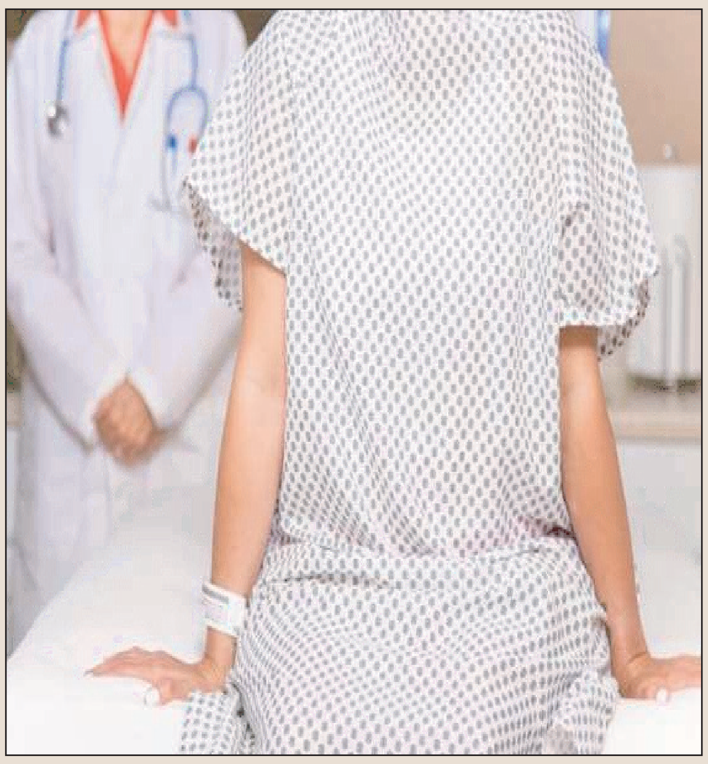

कैंसर एक जानलेवा बीमारी है. यदि इसका समय रहते इलाज शुरू ना किया जाए तो कई गंभीर मामलों में व्यक्ति की जान चली जाती है. बॉडी में ट्यूमर सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ सिर्फ एक बॉडी पार्ट के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर के लिए खतरे की घंटी बन सकती है. कैंसर के कुछ ऐसे प्रकार हैं, जो सिर्फ महिलाओं को इनफेक्ट कर सकते हैं. ऐसे में महिलाओं में कैंसर की समस्या ज्यादा खतरनाक हो सकती है. ओवरीज, कोख या वेजाइना जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर असर करने वाले ये गाइनेकोलॉजिकल कैंसर ढेरों बड़ी परेशानियों का कारण बन सकते हैं. सही समाधान के लिए सही समय पर बीमारी की पहचान कर, सही इलाज कराना जरूरी है. दवाइयों के साथ सही ट्रीटमेंट की मदद से इन परेशानियों से निजात पाई जा सकती है. आइए जानते हैं 5 तरह के गाइनेकोलॉजिकल कैंसर में कौन से आम लक्षण देखे जाते हैं:

एमडैंडरसन डॉट ओआरजी के अनुसार, वुलवर कैंसर के अलावा सभी गाइनेकोलॉजिकल कैंसर में ब्लीडिंग की समस्या देखने को मिलती है. वेजाइना से किसी भी तरह के डिस्चार्ज या ब्लीडिंग को नजरंदाज करना घातक साबित हो सकता है. पेट दर्द के साथ ही कमर दर्द भी किसी बड़े खतरे की दस्तक हो सकती है. ऐसे में सही समय डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले लें.

-बार-बार पेशाब आना किसी गंभीर स्थिति की ओर इशारा हो सकता है. लगातार टॉयलेट जाने की शिकायत कैंसर के साथ ही अन्य परेशानियों का भी लक्षण हो सकती है. ऐसे में जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह करा लें.

-वेजाइना या दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में खुजली, जलन और ज्यादा सेंसटिविटी कैंसर का लक्षण हो सकती है. इन्फेक्शन में भी ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं, ऐसे में इन्हें इग्नोर करने का रिस्क लेने से बचें.

-सेक्स के दौरान या बाद में ज्यादा असामान्य दर्द महसूस होने पर जरूरी टेस्ट अवश्य करा लें. ये दर्द गाइनेकोलॉजिकल कैंसर के शुरुवाती लक्षणों में शुमार है.

-पेडू या पेल्विक एरिया में दर्द होना कैंसर की ओर संकेत करता है. बार-बार इस तरह का दर्द होने पर डॉक्टर को अवश्य दिखा लें नहीं तो समस्या के गंभीर होने की संभावना बढ़ जाती है.

-खाना खाने में असहजता, पेट जल्दी भर जाना, भूख कम लगना या सूजन भी गाइनेकोलॉजिकल कैंसर का संकेत हो सकता है. ऐसे में घबराने की जगह सही उपचार का ख्याल करें.

विंटर में इन चीजों को कहें न , सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादातर महिलाएं हेल्दी डाइट चार्ट फॉलो करती हैं. डाइटिशियन भी सर्दियों में घी, ड्राई फ्रूट्स, गुड़, अदरक, शकरकंद, गाजर, सरसों का साग और केसर जैसी चीजों को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. सर्दियों के दौरान ज्यादातर महिलाएं आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी ठंडी चीजें भी खाना पसंद करती हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्दियों में ठंडी चीजें खाने से सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं. आइए आपको बताते हैं सर्दी में ठंडी चीजों का सेवन करने के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में.

पेट की प्रॉब्लम्स

हेल्थशॉट्स के अनुसार सर्दियों में ठंडा खाना खाने से आपको पेट से जुड़ी कई समस्याएं देखने को मिल सकती हैं. मसलन सर्दियों में ठंडी चीजों का सेवन करने से आपको पेट में सूजन, ऐंठन, पेट फूलना, थकान, बॉडी में शॉक महसूस होना और पाचन तंत्र वीक होने जैसी परेशानियां हो सकती हैं.

शरीर का तापमान कम होना

सर्दी के मौसम में बाहर का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है. ऐसे में ठंडी चीजें खाने से आपकी बॉडी का टेंप्रेचर भी कम होने लगता है. जिससे ब्लड सर्कुलेशन पर बुरा असर पड़ता है और आपका खून जम भी सकता है.

गले में हो सकता है इंफेक्शन

जानकारों के अनुसार सर्दियों में ठंडा खाना खाने से आपको गले में थ्रोट इंफेक्शन हो सकता है. खासकर सर्दी के मौसम में कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडे जूस पीने से आपको गले में खुजली, जलन और इरिटेशन होने लगती है. ऐसे में गले का खास ख्याल रखने के लिए आप गर्म दूध, सूप, नट्स, मसाले और हर्ब्स का सेवन कर सकते हैं.

जुकाम होने का खतरा

सर्दी के मौसम में बॉडी काफी सेंसटिव हो जाती है. ऐसे में ठंडी चीजों का सेवन करना बीमारी को बुलावा देने जैसा होता है. बता दें कि सर्दियों के दौरान ठंडी चीजें खाने से आप खांसी, जुकाम, बुखार और सीजनल फ्लू जैसी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं.

पाचन पर पड़ेगा बुरा असर

सर्दियों में ठंडी चीजों का सेवन पाचन तंत्र को भी खासा प्रभावित करता है. दरअसल ठंडी चीजें काफी हैवी होती है. जिसे पचाने में आपको काफी दिक्कत आ सकती है. वहीं पाचन तंत्र कमजोर होने से आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है.

नशे की हालत में भी महिलाएं सनकी, लंपट पुरुषों की कर सकती हैं पहचान : रिसर्च

शराब पीना न सिर्फ सेहत के लिए हानिकारक होता है बल्कि ये हमारी मानसिक स्थिति को भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है. शराब पीने के बाद व्यक्ति सही और गलत का निर्णय लेने तक में सक्षम नहीं रहता है, ऐसी सूरत में फिर चाहे पुरुष हो या महिला उसका आसानी से फायदा उठाया सकता है. नशे की हालत में सही व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता भी प्रभावित होती है. वैसे तो ये बात ठीक ही है लेकिन नशा की हुई महिलाओं के मामले में ये बात पूरी तरह से खरी उतरती नज़र नहीं आती है. हाल ही में एक रिसर्च में सामने आया है कि नशे की हालत में होने के बावजूद भी महिलाएं सनकी (Psychopaths) और धूर्त एवं दुष्ट प्रवत्ति (Narcissists) के लोगों की पहचान कर सकती हैं.

यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की डॉ. गेल ब्रेवर (Dr. Gayle Brewer) और उनकी टीम ने ये रिसर्च की है. Vice की खबर के अनुसार रिसर्च में ये पता लगाने की कोशिश की गई कि शराब पीने के बाद महिलाएं पुरुषों के व्यक्तित्व को कितना पहचान पाती हैं.

फोटो के जरिए कराई पर्सनैलिटी की पहचान

शराब के नशे में होने के बावजूद महिलाओं ने सनकी, धूर्त और लंपट पुरुषों की पहचान की. इस दौरान रिसर्च टीम ने महिलाओं को वोदका और लेमोनेट पिलाया. बता दें कि ये रिसर्च 96 महिलाओं पर की गई थी, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 26 साल के बीच थी. रिसर्च के दौरान नशा की हुई महिलाओं को कुछ पुरुषों के फोटोग्राफ दिखाए गए जिनके चेहरों से छेड़छाड़ की गई थी जिससे वे सनकी और धूर्त नज़र आएं. डॉ. ब्रेवर ने बताया कि 'हमने रिसर्च के दौरान क्लिनिकली डाइग्नोज किए गए किसी पुरुष का उपयोग नहीं किया, इसके बजाय उन फोटोज़ का उपयोग किया जिसमें पुरुष ज्यादा लंपट, सनकी या धूर्त नजर आए.' रिसर्च के दौरान पाया गया कि जिन पुरुषों के चेहरे ज्यादा सनकी या धूर्त नजर आए महिलाओं ने उन्हें नापसंद किया और उनके बारे में नकारात्मक राय दी.

डॉ. ब्रेवर ये भी कयास लगाती हैं कि महिलाओं में दुष्ट प्रवत्ति के पुरुषों को पहचानने की एक इनबिल्ट, अनकांशियस क्षमता एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज है. वे ये भी कहती हैं कि आप अल्कोहल को अपने निर्णय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं.

शराब के नशे में होने के बावजूद महिलाओं ने सनकी, धूर्त और लंपट पुरुषों की पहचान की. इस दौरान रिसर्च टीम ने महिलाओं को वोदका और लेमोनेट पिलाया. बता दें कि ये रिसर्च 96 महिलाओं पर की गई थी, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 26 साल के बीच थी. रिसर्च के दौरान नशा की हुई महिलाओं को कुछ पुरुषों के फोटोग्राफ दिखाए गए जिनके चेहरों से छेड़छाड़ की गई थी जिससे वे सनकी और धूर्त नज़र आएं.

इनसाइड

1.8 डिग्री तक लुढ़का शुक्रवार सुबह का पारा; ठंड से कांपे लोग, शीत लहर का प्रकोप जारी

नईदिल्ली। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। चार केंद्रों सफदरजंग, आयानगर, रिज व लोदी रोड में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों ठंड का कहर अपने चरम पर है। गुरुवार को 2.2 डिग्री न्यूनतम तापमान के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आज दिल्ली में 1.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया जो सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। शुक्रवार की सुबह दिल्ली के आयानगर का तापमान 1.8 डिग्री दर्ज किया गया। इस तरह लगातार तीसरे दिन दिल्ली की सुबह कई पहाड़ी राज्यों से भी ठंडी रही। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। चार केंद्रों सफदरजंग, आयानगर, रिज व लोदी रोड में शीत लहर का प्रकोप है। यही नहीं गुरुग्राम का भी तापमान आज तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अभी सात जनवरी तक शीतलहर का अनुमान जताया है। उसके बाद न्यूनतम व अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। अधिकतम तापमान 18-20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री तक पहुंच जाएगा।

गुरुवार को लुढ़का पारा

गिरते पारे के साथ समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़के की ठंड जारी है। आज भी दिल्ली की सुबह बेहद सर्द है। गुरुवार को पारा लुढ़क कर तीन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से दिल्ली कई पहाड़ी क्षेत्रों से भी अधिक सर्द रही। हालांकि कल से राहत की उम्मीद है। दिल्ली में भीषण सर्दी और कोहरे के बीच लोग खुद को गर्म रखने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं।

कल से उत्तर-पश्चिम भारत में सुधरेंगे हालात

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के चलते सात जनवरी से उत्तर-पश्चिम भारत से हालात सुधरने शुरू होंगे। पहाड़ों से आती बर्फीली हवाओं ने मैदानी क्षेत्र में लोगों को घर में दुबकने को मजबूर कर दिया।

कोहरे से 14 ट्रेनें प्रभावित

रेलवे प्रवक्ता के मुताबिक कम से कम 12 ट्रेनें डेढ़ से छह घंटे तक देरी से नई दिल्ली पहुंचीं और दो का परिचालन समय बदलना पड़ा। दिल्ली हवाई अड्डे ने भी कोहरे के कारण कम दृश्यता का अलर्ट जारी किया।

दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने दायर की दूसरी चार्जशीट, 12 लोगों के नाम शामिल

नईदिल्ली। शराब घोटाला दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। भाजपा ने शराब घोटाले को लेकर कई स्टिंग वीडियो भी जारी किए थे। इसी बीच अब शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी चार्जशीट दायर की है। राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर बीते साल जमकर बवाल देखने को मिला था। शराब घोटाले को लेकर भाजपा (BJP) और आम आदमी पार्टी के बीच वार-पलटवार भी देखने को मिला था। शराब घोटाला दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। भाजपा ने शराब घोटाले को लेकर कई स्टिंग वीडियो भी जारी किए थे। इसी बीच अब शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी चार्जशीट दायर की है। ईडी ने ये चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। बता दें कि दूसरी चार्जशीट में ईडी ने 12 आरोपी बनाए हैं। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब आबकारी नीति मामले में दूसरी चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में 12 अभियुक्तों के नाम शामिल हैं - 5 गिरफ्तार व्यक्ति (विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा) और 7 कंपनियां। आगे की जांच जारी है।

एमसीडी मेयर इलेक्शन: हंगामा क्यों बरपा? आप को किस बात का डर, क्या बीजेपी बना लेगी अपना मेयर?

मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास नगर निगम में पूर्ण बहुमत है, लेकिन इसके बाद भी वे हंगामा कर रहे हैं

एनटीवी संवाददाता

नगर निगम के लिए होने वाले मेयर के चुनाव में 250 पार्षद, सात लोकसभा सांसद, तीन राज्यसभा सांसद और दिल्ली विधानसभा के 14 विधायक वोट देते हैं। कुल 274 वोटों में बहुमत पाने वाले प्रत्याशी को मेयर घोषित किया जायेगा...

नई दिल्ली। शुक्रवार को एकीकृत दिल्ली नगर निगम के मेयर (MCD Mayor Election) का चुनाव होना तय था। लेकिन जैसे ही पीठासीन अधिकारी ने मनोनीत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना शुरू किया, हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने निर्वाचित सदस्यों से पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ ग्रहण करने का विरोध किया। उसका आरोप है कि भाजपा नियमों में बदलाव कर मेयर पद हथियाना चाहती है। वहीं, भाजपा सदस्यों को अपने अनुसार शपथ ग्रहण करने पर अड़ी थी। दोनों दलों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि नेताओं के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसमें दोनों दलों के कुछ नेताओं को चोटें आई हैं। मारपीट के लिए दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। सदन के बाहर अंबेडकर की मूर्ति के पास पहुंचकर भी दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल, इस पूरे विवाद के पीछे मेयर पद पर कब्जा करने की कोशिश बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने अमर उजाला से कहा कि भाजपा ने नियमों के खिलाफ जाकर पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया। परंपरा के अनुसार सदन में बहुमत प्राप्त दल से ही पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, लेकिन भाजपा ने उपराज्यपाल के माध्यम से अपना पीठासीन अधिकारी नियुक्त करवा दिया।
अब इनके माध्यम से परंपरा से उलट जाकर निर्वाचित सदस्यों से पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ ग्रहण करवा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नियमों में बदलाव कर मनोनीत सदस्यों को भी मेयर पद के लिए वोटिंग में मतदान का अधिकार देना चाहती है। यही इस पूरे विवाद की जड़ है। आप सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश है जिसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।

बहुमत है तो डर क्यों?

भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने स्वयं को अराजक और कानून-व्यवस्था को न मानने वाला बताया था। आज उनके नेताओं ने उनकी बात को सही साबित कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में मारपीट की। उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता करने की कोशिश की।
मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास नगर निगम में पूर्ण बहुमत है, लेकिन इसके बाद भी वे हंगामा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी के पार्षदों पर बिकने का आरोप लगा रहे हैं। शायद उन्हें पता है कि उनके पार्षद उनके साथ नहीं हैं। यही कारण है कि वे हंगामा कर मेयर चुनाव में बाधा डालना चाहते हैं।

अंकगणित किसके साथ?

नगर निगम के लिए होने वाले मेयर के चुनाव में 250 पार्षद, सात लोकसभा सांसद, तीन राज्यसभा सांसद और दिल्ली विधानसभा के 14 विधायक वोट देते हैं। कुल 274 वोटों में बहुमत पाने वाले प्रत्याशी को मेयर घोषित किया जायेगा। इसमें भाजपा के पास 104 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद और एक विधायक हैं। इस प्रकार भाजपा के पास 112 वोट हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद, तीन राज्यसभा सांसद और 13 विधायकों का वोट है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी के पास 150 सदस्यों का मत है और उसका मेयर बनना लगभग तय है। चूंकि, नगर निगम के मेयर के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता, किसी भी पार्टी का कोई सदस्य किसी भी प्रत्याशी को वोट कर सकता है। इसके लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन मनोनीत सदस्य अन्य सेक्टोरल कमेटियों के चयन प्रक्रिया में वोट कर सकते हैं। इससे आम आदमी पार्टी को क़ई कमेटियों में अधिकतर खोना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि असली विवाद इसी मामले को लेकर है।

आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, भाजपा का दावा- नैतिक रूप से हार चुकी है आप

नई दिल्ली। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि सदन में भाजपा का खूनी खेल शुरू हो गया है। चुनाव में जनता ने हरा दिया तो भाजपा सदन में गुंडागर्दी कर रहीं है। वहीं, मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को डर किस बात का है? क्या नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी हार चुकी है?

दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी थी। लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी के फैसले के खिलाफ हंगामा शुरू किया। इस बीच भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है।

आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है: मनोज तिवारी

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा और आप पार्षदों के बीच हंगामे को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी को डर किस बात का है? क्या नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी हार चुकी है? क्या उनको समझ आ गया है कि उनके पार्षद उनका साथ नहीं देंगे? मेयर चुनने के पहले ही इस तरह का हंगामा, ये निश्चित रूप से दिखाता है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है।

आदेश गुप्ता ने बोला हमला

भाजपा नेता आदेश गुप्ता ने कहा कि अराजकता आप की मानसिकता में निहित हो चुकी है! आज सदन में गुंडागर्दी और मारपीट करके लोकतंत्र का खिलवाड़ करने का कुकर्म जो आप के गुंडों ने किया है, यह इनकी नैतिक स्तर पर हार है।

भाजपा सदन में गुंडागर्दी कर रहीं है: संजय सिंह

वहीं, आप नेता संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सदन में भाजपा का खूनी खेल शुरू हो गया है। चुनाव में जनता ने हरा दिया तो भाजपा सदन में गुंडागर्दी कर रहीं है। दो बार के आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण कुमार पर सदन के अंदर भाजपा वालो ने किया जानलेवा हमला। इस काम में कांग्रेस का हाथ भाजपा के साथ।

> *आप नेता संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सदन में भाजपा का खूनी खेल शुरू हो गया है। चुनाव में जनता ने हरा दिया तो भाजपा सदन में गुंडागर्दी कर रहीं है। दो बार के आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण कुमार पर सदन के अंदर भाजपा वालो ने किया जानलेवा हमला।*

मनीष सिसोदिया ने भाजपा को घेरा

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एमसीडी में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए और कितना गिरोगे भाजपा वालो! चुनाव टाले, पीठासीन अधिकारी की गैरकानुनी नियुक्ति, मनोनीत पार्षदों की गैरकानुनी नियुक्ति, और अब जनता के चुने पार्षदों को शपथ न दिलवाना'. अगर जनता के फैसले का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर चुनाव ही किसलिए?

मुझे जान से मारने की कोशिश की गई: आप पार्षद प्रवीण राणा

आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण राणा ने सदन में मारपीट करने का आरोप लगाया है। आप सांसद संजय सिंह और विधायक सौरभ भारद्वाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ में चोट दिखाते हुए प्रवीण ने कहा कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। उनका गला दबाने की कोशिश की गई। इस दौरान विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानती है। वहीं, सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने सभी कानूनों को दरकिनार करते हुए मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने की कोशिश की जबकि पहले चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलाया जाता है। आप पार्षद प्रवीण कुमार ने कहा कि भाजपा गुंडागर्दी कर रही है। सबसे पहले मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण कराया जा रहा था। जब हमने इसका विरोध किया और पहले निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण कराने की मांग की तो हंगामा हो गया।

भाजपा बेईमानी से एमसीडी में कब्जा करना चाहती है: सौरभ भारद्वाज

आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी के इतिहास में आज तक कभी सदन में नॉमिनेटेड पार्षद ने वोट नहीं डाली। भाजपा बेईमानी से एमसीडी में कब्जा करना चाहती है। बीजेपी वालों तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे।

दुर्गेश पाठक ने बोला हमला

आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी के इतिहास में आज तक कभी नॉमिनेटेड पार्षद की पहले शपथ और वोटिंग नहीं हुई है। भाजपा वालों तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं होने देंगे।

चार नामित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की

शुक्रवार को केवल चार नामित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की, बाकी सदस्य सदन की अगली बैठक में शपथ लेंगे।

कंझावला केस : मामले में आया नया मोड़, हादसे के वक्त 5 नहीं कार में थे केवल 4 लोग

एनटीवी संवाददाता

नईदिल्ली। देश को दहला कर रख देने वाले कंझावला कांड में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसमें रोजाना कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला खुलासा अब हुआ है, जिससे जांच की दिशा बदलने के कयास हैं। वारदात वाले दिन से लेकर 5 जनवरी तक जो पुलिस ये कह रही थी कार में पांच लोग सवार थे, वही पुलिस अब कह रही है कि कार में सिर्फ चार लोग थे। जानिए कौन है वो आरोपी जिसके होने की बात पहले की जा रही थी लेकिन अब पता चला है कि वह हादसे के वक्त कार में था ही नहीं।

मामले की शुरुआती जांच में आरोपी बनाए गए पांच लोग पुलिस को लगातार अलग-अलग बयान दे रहे हैं। ऐसे में सही तथ्य धीरे-धीरे कर सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि यह बात अब सामने आई है कि वारदात वाली रात कार में सिर्फ चार लोग सवार थे। यह बात एक ताजा सीसीटीवी फुटेज से भी स्पष्ट हो गई है। दरअसल वारदात वाली रात दीपक अपने घर पर ही था उसे बाद में बुलाया गया था।

जैसा कि पुलिस ने गुरुवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था वारदात वाली रात कार दीपक नहीं अमित चला रहा था। अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। पूरी घटना जब अमित ने अपने भाई अंकुश को बताई तो उसी ने दीपक को बुलाकर उसके ड्राइविंग करने की बात कहने का सुझाव दिया था। इसके बाद दीपक को घर से बुलाया गया।

ताजा सीसीटीवी फुटेज में ड्राइवर को छोड़कर अन्य तीन आरोपी कार से उतरते दिखते हैं। वहीं एक अन्य शख्स जो कार आने से पहले से वहां खड़ा था वह जाकर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। बताया जा रहा है कि यही व्यक्ति आरोपी दीपक है, जिसके कार चलाने का दावा किया जा रहा था।

कार मालिक आशुतोष ने भी पुलिस को शुरुआती जांच में यही बताया था कि उसके पास से दीपक कार ले गया था, जबकि सच यह था कि उससे अमित कार लेकर गया था और घटना को उसी ने अंजाम दिया। मालूम हो कि कार मालिक आशुतोष को छठा आरोपी बनाया गया है जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आशुतोष की कार लेकर आरोपी गए थे। आशुतोष पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक वारदात के समय कार में केवल 4 आरोपी थे, दीपक घर में था, लेकिन उसे अमित ने बाद में बुलाया था।

चश्मदीद निधि को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा, परिवार से है बेदखल और आगरा में दर्ज है एक केस

कंझावला कांड की एकमात्र गवाह निधि जब से इस मामले से जुड़ी उसे और उसके दावों को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठ रहा था कि अगर अंजलि निधि की सहेली थी तो वह कैसे उसे मरता हुआ छोड़कर भाग आई। अगर भागी भी तो उसने पुलिस को समय रहते इसे लेकर कुछ क्यों नहीं बताया। लगभग दो दिन बाद जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तब उसके बारे में पता चल सका। अब इसी निधि को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसकी पुष्टि निधि की मां ने की है। उन्होंने माना है कि निधि के खिलाफ आगरा में एक केस दर्ज है। आगे पढ़ें निधि को लेकर और क्या खुलासे हुए हैं...

निधि की मां ने बातचीत में बताया कि उनकी बेटी को उसके भाइयों ने परिवार से बेदखल कर दिया है। निधि कई साल से अपने परिवार से अलग रह रही है। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने कहा कि वह अपनी सहेलियों के साथ घूमती थी इसलिए भाइयों ने उसे अलग कर दिया लेकिन वह बेटी से मिलने जाती रहती हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी बेटी के खिलाफ कुछ साल पहले आगरा में केस दर्ज हुआ था लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह किस मामले में था। जानकारी के अनुसार निधि के खिलाफ ड्रग्स तस्करी के मामले में आगरा में केस दर्ज है। इस संबंध में अभी पुलिस अधिकारियों से स्पष्टीकरण नहीं मिल सका है। पुलिस निधि को पूछताछ के लिए ले गई है। माना जा रहा है कि इसके बाद पुलिस इन तथ्यों का भी खुलासा कर सकती है। इस बीच निधि के पड़ोसी ने बताया है कि निधि ने उसे धमकी दी है कि उस रात के बारे में किसी से कुछ न कहे।

गुरुवार को अंजलि के परिवार वाले निधि के घर के बाहर आ गए। वहां तैनात पुलिसकर्मियों को उसे घर से बाहर निकालने के लिए कहा। लोगों ने निधि के खिलाफ नारेबाजी की। उस गली में रहने वाले भी अंजलि के परिवार वालों का साथ दे रहे थे। गली वालों ने उसके घर की बिजली की मैन लाइन बंद कर दी। ऐसे में निधि ने पुलिस वालों को अपनी सुरक्षा की मांग की है। उसका कहना है कि उसके घर के बाहर पुलिस वाले जरूर तैनात रहे। उसने लोगों पर हमला करने की आशंका जताई है। निधि के चश्मदीद होने के कारण पुलिस के दो से तीन जवान उसके घर के बाहर 24 घंटे तैनात हैं।

काशी विश्वनाथ और पांच लोकल ट्रेन निरस्त

गाजियाबाद। नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली डाउन काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस और पांच लोकल ट्रेन बृहस्पतिवार को भी निरस्त रही। बुधवार को वाराणसी से नई दिल्ली आने वाली काशी विश्वनाथ निरस्त कर दी गई थी, इसलिए बृहस्पतिवार को डाउन ट्रेन निरस्त रही। इसके अलावा गाजियाबाद से पलवल, दिल्ली, नई दिल्ली और मेरठ जाने वाली लोकल ट्रेन भी निरस्त रही।
सत्याग्रह एक्सप्रेस 28:09 घंटे देरी से गाजियाबाद पहुंची, जबकि नई दिल्ली इंटरसिटी 25:08 घंटे और नई दिल्ली सुपरफास्ट 24:56 घंटे की देरी से पहुंची। बृहस्पतिवार को 14 ट्रेनें एक घंटा से 28 घंटे की देरी पर गाजियाबाद स्टेशन पहुंची। सबसे अधिक उन यात्रियों को हो रही है, जो ट्रेन का सही समय देखकर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं लेकिन 15-15 मिनट देरी की उद्घोषणा होती रहती और ट्रेन दो से ढाई घंटे बाद स्टेशन पर पहुंचती है। ऐसे में महिलाओं और बच्चों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है।

ट्रेन स्थिति

सत्याग्रह एक्सप्रेस 28:09 घंटे
नई दिल्ली इंटरसिटी 25:08 घंटे
नई दिल्ली सुपरफास्ट 24:56 घंटे
सुहेलदेव 8:02 घंटे
ब्रह्मपुत्र मेल 7:59 घंटे
कलिंग उत्कल 3:30 घंटे
अयोध्या कैंट 2:14 घंटे
पद्मावत 2:20 घंटे
लखनऊ सुपरफास्ट 2:13 घंटे
हरिद्वार सुपरफास्ट 2:06 घंटे
उत्कल एक्सप्रेस 1:51 घंटे

करिअर को प्राथमिकता दे अंडाणु सुरक्षित रखवा रहीं महिलाएं

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की रहने वाली 34 साल की युवती की पढ़ाई पूरी होते ही बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी लग गई। करियर के लिए शादी में देरी की। अब मनचाहा वर नहीं मिल रहा। इसलिए, अंडाणु सुरक्षित रखवा लिए हैं ताकि शादी होने पर मां बनने में इनका इस्तेमाल किया जा सके।

यह सिर्फ एक मामला नहीं है। दिल्ली-एनसीआर में सैंकड़ों की संख्या में युवतियां अंडाणुओं को सुरक्षित रखवा रही हैं। इसकी दो मुख्य वजह हैं। युवतियां करिअर को प्राथमिकता दे रही हैं। इसके लिए शादी देरी से कर रही हैं। दूसरा, जो शादी भी कर रही हैं, वे मां बनने के लिए समय ले रही हैं। कम उम्र में अंडाणु की गुणवत्ता बेहतर होती है। इसलिए, इस 25 से 30 की उम्र में अंडाणु सुरक्षित रखवा देती हैं। आईवीएफ सेंटर में एग बैंक खुल गए हैं। इनमें अंडाणु रखे जा रहे हैं। पटेल नगर की युवती निजी एयरलाइंस में एयर होस्टेस है। उसने बताया, शादी तो हो गई है लेकिन मां बनने से करिअर में बाधा आ जाएगी। जब तक एयरलाइंस में दफ्तर का काम नहीं मिल जाता है, मां नहीं बनना चाहूंगी। इसलिए, अंडाणु सुरक्षित रखवा दिए हैं। कम उम्र में अंडाणु की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। इसलिए करिअर की प्राथमिकता या शादी में देरी होने पर महिलाएं अंडाणु सुरक्षित करा रही हैं।

ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर, दो लोगों की दर्दनाक मौत

एनटीवी न्यूज

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर-141 स्थित निर्माणाधीन अंडरपास के पास एक तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती-युवक की अस्पताल में इलाज शुरू होने से पहले ही मौत हो गई वहीं घायल दो युवकों का इलाज शारदा अस्पताल में चल रहा है।

नोएडा: नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर-141 स्थित निर्माणाधीन अंडरपास के पास बुधवार रात एक तेज रफ्तार कैंटर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस पर सगे भाई-बहन सहित चार लोग सवार थे। हादसे में एक युवती व एक युवक की अस्पताल में इलाज शुरू होने से पहले ही मौत हो गई है। वहीं घायल दो युवकों का इलाज शारदा अस्पताल में चल रहा है। एक्सप्रेसवे कोतवाली पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच कर रही है। आरोपित कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाइक सवार ने हेलमेट भी नहीं पहना था।

एक ही बाइक पर चार लोग कर रहे थे सवारी

जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद के पचोकरा थाना अंतर्गत लालगढ़ी गांव के शोभित (23), भावना (19), सोनू (18) व कौशलेंद्र (24) सेक्टर-49 स्थित बरौला गांव में किराये के मकान में रहते थे। कौशलेंद्र व भावना सगे भाई-बहन हैं। सभी ग्रेटर नोएडा के चाई-फाई स्थित एक रेस्तरां में काम करते थे। बुधवार रात करीब 1:45 बजे चारों एक ही प्लेटिना पर बरौला स्थित घर आ रहे थे। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एडवांट के सामने ग्रेटर नोएडा की ओर से आ रहे एक फर्नीचर से भरे कैंटर ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। जिसमें चारों गंभीर रूप से घायल हो गए।

दो लोगों की हालत गम्भीर

108 एंबुलेंस सेवा प्रभारी दीपक सिंह ने कहा कि सूचना के तुरंत बाद घायलों को इलाज के लिए सेक्टर-30 स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज से पूर्व डाक्टरों ने भावना व शोभित को मृत घोषित कर दिया। सिर में गंभीर चोट आने के कारण दोनों की मौत हुई है। वहीं अन्य दो घायलों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई है। उन्हें ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक कौन चला रहा था, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। दोनों की हालत गंभीर है।

पुलिस ने दी ये जानकारी

एडिशनल डीसीपी का कहना है कि घायलों के उपचार में हर संभव मदद की जाएगी। हादसे में मृतक भावना कौशलेंद्र की छोटी बहन थी। हादसे के बाद चालक कैंटर छोड़कर फरार हो गया था। टक्कर इतनी तेज थी कि कैंटर का अगला हिस्सा व बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। शोभित के बड़े भाई शिवकुमार की तहरीर पर कैंटर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया गया है। फरार कैंटर चालक को वाहन मालिक से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित की पहचान फिरोजाबाद के अरुण प्रताप के रूप में हुई है।

अंडरपास के निर्माण में देरी से बढ़ रहे हादसे

जिस जगह पर हादसा हुआ है, वहां अंडरपास निर्माण कार्य के कारण बैरिकेड लगाए गए हैं। अंडरपास निर्माण में देरी के कारण आए दिन हादसे के साथ जाम की स्थित बनती है। व्यस्त समय में दो किलोमीटर लंबा जाम लगता है। कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार का कहना है कि आशंका है कि कैंटर चालक तेज रफ्तार में रहा होगा। इस दौरान कोहरा भी था। अंडरपास के ऊपर बाटलनेक के कारण बैरिकेड की टक्कर से बचने के लिए कैंटर चालक ने तेजी से दायीं तरफ वाहन मोड़ा। अंडरपास के ऊपर कैंटर की बाइक से टक्कर हो गई। एडिशनल डीसीपी नोएडा आशुतोष द्विवेदी का कहना है कि दुर्घटनास्थल वाली जगह पर बैरिकेड आदि जगह पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, जिससे हादसे की संभावना कम हो सके।

इनसाइड

फर्जी कंपनी बनाकर 2.24 करोड़ की किताबें मंगाकर की धोखाधड़ी

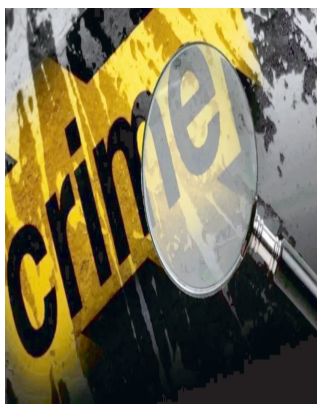

साहिबाबाद। औद्योगिक क्षेत्र साइट-4 के उद्यमी सुनील कुमार ने महाराष्ट्र की फर्जी कंपनी के नौ लोगों पर 2.24 करोड़ की किताबें मंगाकर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि शातिरों ने किताबें मंगाकर उसका भुगतान नहीं किया। लिंक रोड थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुनील कुमार ने बताया कि तीन नवंबर 2022 को उनके पास महाराष्ट्र की कंपनी ने किताबें लेने के लिए संपर्क किया था। इसमें उन्हें अलग-अलग जगह पर किताबें देने की एवज में रकम अदा करने के लिए कहा गया था। इस बीच कोरोना महामारी का बहाना बनाकर उन्होंने रकम कुछ महीनों बाद देने के लिए कहा। इसके बाद दोबारा से किताब का ऑर्डर दे दिया। करीब दो सालों में शातिरों ने उनसे 2.24 करोड़ की किताबें सप्लाई करा लीं लेकिन भुगतान देने के लिए टालते रहे। उन्होंने अपने स्तर से मामले की जांच कराई तो फर्जी कंपनी का भंडाफोड़ हुआ। अब लिंक रोड थाने में कंपनी के नौ लोगों पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा कराया है। एसीपी पूनम मिश्रा ने बताया कि मनोरंजन कुमार, अनमोल डी बोराडे, आनंद वी पलासकर, देवानंद तिवारी, राजेश रामाराव, रितेश तिवारी, सुशील कुमार दुबे, वैशुशंकर राव काकरीवार और विनीत कृष्ण मुरारी द्विवेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रहे हैं। उद्यमी ने बताया कि फर्जी कंपनी चलाने वाले सभी नौ आरोपियों को उनकी कंपनी में महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों की जिम्मेदारी दी हुई थी। इनको वितरक और व्यापारी समेत अन्य लोगों को किताबें सप्लाई करने के लिए भुगतान किया जाता था लेकिन इन आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों की दुकान पर किताबें सप्लाई कर धोखाधड़ी की है।

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का किया निरीक्षण, वैक्सीनेशन बंद होने पर कहा- दो दिनों में मिलेगा टीका

नोएडा के सेक्टर-39 के कोविड अस्पताल में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक गुरुवार को नोएडा पहुंचे। सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन के अभाव में निश्शुल्क कोरोना वैक्सीनेशन के बंद होने पर उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में जिले में वैक्सीन आ जाएगी।

नोएडा। सेक्टर-39 स्थित कोविड अस्पताल में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक गुरुवार को नोएडा पहुंचे। सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन के अभाव में निश्शुल्क कोरोना वैक्सीनेशन के बंद होने पर उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में जिले में वैक्सीन आ जाएगी। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा हुई है। गौतमबुद्धनगर को पर्याप्त वैक्सीन मिलेगी।
प्रदेश स्तर पर अलग-अलग जिलों में आपूर्ति के लिए वैक्सीन की दस लाख डोज मिलनी है। जल्द लखनऊ से कोरोना वैक्सीन नोएडा में भी सीएमओ कार्यालय भेजी जाएंगी। गौरतलब है कि अभी वैक्सीन के अभाव में सरकारी केंद्रों से लोग वापस लौटने पर मजबूर हैं। सेक्टर-30 स्थित जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन केंद्र में तो रैन बसेरा बना दिया गया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सेक्टर-30 स्थित जिला अस्पताल को सेक्टर-39 में इसी महीने शुरू हो जाएगा।
जिला अस्पताल को नई इमारत में शिफ्ट करने और नई सुविधाओं के साथ शुरू करने का खाका तैयार कर लिया है। आंतरिक रूप से तारीख भी तय कर ली है। अभी तारीख की घोषणा नहीं कर रहे हैं। रैंप और बिजली फीडर को लेकर छोटी सी समस्या है। जिसका समाधान करने के लिए जल्द नोएडा प्राधिकरण और बिजली विभाग के साथ बैठक होगी। अस्पताल के शुभारंभ की तारीख घोषित कर दी जाएगी। जिला अस्पताल में फिजीशियन नहीं होने के सवाल पर कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संविदा के आधार पर चिकित्सकों की भर्ती करने का अधिकार दिया है। वह वाक इन इंटरव्यू आयोजित कर सकते हैं। डाक्टरों का चयन कर राज्य सरकार से अनुमति (अप्रूवल) ले सकते हैं। इस प्रक्रिया के आधार पर जल्द जिला अस्पताल में चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। इसके बाद डाक्टरों की कमी नहीं रहेगी।

कोविड से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा

उपमुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे कोविड अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेरठ मंडल के अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. राजेंद्र कुमार के अलावा गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर के सीएमओ से अपने-अपने जिलों में कोरोना से निपटने को लेकर की गई तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना की नई लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार पर्याप्त इंतजाम कर रही है। इसी सिलसिले में नोएडा के कोविड-19 अस्पताल का जायजा लिया है। सुविधाओं की उपलब्धता पर गौर की गई है। एनसीआर में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैलता है। सबसे ज्यादा खतरा यहीं है। लिहाजा, स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। हम किसी भी समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आक्सीजन, बेड, दवा, उपकरण, डाक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की जानकारी ली है।

अग्निवीरों पर राहुल के बयान को बताया दुखद

उत्तर प्रदेश के बागपत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सेना में अग्निवीर की भर्ती को लेकर दिए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उपमुख्यमंत्री ने राहुल के बयान को दुखद बताया है। हालांकि राहुल की टीशर्ट वाले अपने खुद के बयान पर उपमुख्यमंत्री ने नोएडा में पहुंचने के बाद चुप्पी साधी रखी।

संविदाकर्मियों ने सौंपा ज्ञापन

उपमुख्यमंत्री करीब डेढ़ घंटे अस्पताल में रहे। इस दौरान उन्हें संविदा के तहत तैनात नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संविदाकर्मी की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। जिससे हर माह ठेका बढ़ाने की अनुमति न लेनी पड़े।

बैठक के दौरान यह रहे मौजूद

कोविड अस्पताल में समीक्षा बैठक के दौरान दादरी विधायक तेजपाल नागर, एमएलसी श्रीचंद शर्मा, भाजपा महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, सीएमओ डा. सुनील कुमार शर्मा, सीएमएस डा. पवन कुमार, सभी एसीएमओ मौजूद रहे।

बर्फीली हवाओं ने नोएडावासियों को ठिठुरने पर किया मजबूर, कड़ाके की शीतलहर से जनजीवन प्रभावित

नोएडा के औद्योगिक नगरी में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। बृहस्पतिवार को न्यूनतम पारा पांच डिग्री से नीचे रहा। वहीं अधिकतम पारा भी 15 डिग्री सेल्सियस रहा। रात का पारा गिरने से सुबह और देर रात सर्दी की मार पड़ रही है।

नोएडा। औद्योगिक नगरी में निचला तापमान लगातार गिर रहा है। बृहस्पतिवार को न्यूनतम पारा पांच डिग्री से नीचे रहा। वहीं अधिकतम पारा भी 15 डिग्री सेल्सियस रहा। रात का पारा गिरने से सुबह और देर रात सर्दी की मार पड़ रही है। बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे दिन कोल्ड-डे (ठंडे दिन) स्थित बनी रही। आंकड़ों की माने तो बुधवार की रात इस वर्ष की अबतक की सबसे सर्द रात रही।

छाया रहा घना कोहरा

शहर में सुबह घना कोहरा रहा। कड़ाके की शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। दिन और रात के तापमान में अंतर कम हो जाने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिन के तापमान में ज्यादा गिरावट और आसमान में बादल छाए रहने से स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई। लगातार तीसरे दिन कड़ाके की सर्दी ने शहरवासियों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। सुबह से शाम तक लोग धूप को तरस गए।

ठंड से बचने के लिए घर से नहीं निकले लोग

दोपहर एक बजे बजे के आसपास सूर्य के दर्शन तो हुए लेकिन कोहरे की चादर के पीछे छवि भर दिखी। शाम होते ही सड़क के किनारे लोग अलाव तापते दिखे। चाय की स्टालों पर अधिक भीड़ नजर आई। हालांकि अंधेरा छाने के बाद लोग अपने घरों में दुबक गए। जरूरी काम होने के बाद ही घरों से बाहर निकले। मौसम विभाग के अनुसार जाते हुए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यह स्थिति बनी है जो फिलहाल 48 घंटे तक जारी रह सकती है। कोहरे की मोटी परत ने धूप की गर्मी को धरती तक पहुंचने से रोक दिया। ऊपर से पछुआ हवाएं गलन बढ़ा रही हैं। बृहस्पतिवार को भी हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रतिघंटा के करीब रही। इसकी दिशा उत्तर पश्चिम रही। उत्तर पश्चिम हवाओं के चलने से गलन ज्यादा महसूस हो रही है। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 100 चल रहा है।

देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा ग्रेटर नोएडा

बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 383 व नोएडा का 349 रहा। यह वायु प्रदूषण की बहुत खराब श्रेणी हैं। ग्रेटर नोएडा देश के साथ ही एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर रहा। गत दिवस के मुबाकले एक्यूआइ में बढ़ोतरी हुई।

CNG के साथ आई मारुति की पावरफुल SUV, भर-भर के मिलेगा माइलेज

सीएनजी- पावर्ड मॉडल में, इंजन 87.83 पीएस का अधिकतम पावर आउटपुट और 121.5 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट पैदा करता है. हालांकि, प्योर-पेट्रोल मोड में, इंजन अधिकतम 100.6 पीएस की पावर और 136 एनएम का अधिकतम टॉर्क देता है, जो ग्रैंड विटारा के पेट्रोल-पावर्ड वेरियंट की तुलना में लगभग 2.5 पीएस कम है.

सीएनजी से चलने वाली कारों की लोकप्रियता को भुनाने के लिए, मारुति सुजुकी ने अपनी प्रमुख एसयूवी, ग्रैंड विटारा के सीएनजी-पावर्ड वेरिएंट को लॉन्च किया है. नई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सीएनजी अब दो वेरिएंट्स – डेल्टा और जेटा में उपलब्ध है, दोनों स्टैंडर्ड के रूप में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आते हैं. जहां ग्रैंड विटारा सीएनजी के डेल्टा वेरिएंट की कीमत 12.85 लाख रुपये है, वहीं इसका जेटा वेरिएंट अब 14.84 लाख रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है.

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सीएनजी का पावरट्रेन 1.5-लीटर 4-सिलेंडर स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड K15C पेट्रोल इंजन पर आधारित है, जो एसयूवी के शुद्ध-पेट्रोल वेरिएंट में पहले से ही उपलब्ध है.

ग्रैंड विटारा एस-सीएनजी

ग्रैंड विटारा एस-सीएनजी की शुरुआत की घोषणा करते हुए शशांक श्रीवास्तव, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, मार्केटिंग एंड सेल्स, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने कहा, "सितंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से, ग्रैंड विटारा को भारतीय कन्ज्यूमर्स से शानदार प्रतिक्रिया मिली है, इसकी SUV अपील को भविष्य के लिए तैयार कई पावरट्रेन से कॉम्प्लिमेंट किया गया है. एस-सीएनजी विकल्प की शुरूआत ने ग्रैंड विटारा की अपील को और बढ़ा दिया है. ग्रैंड विटारा एस-सीएनजी हमारी ग्रीन-पॉवरट्रेन पेशकशों को एक्सपेंड करने की हमारी आक्रामक योजना में योगदान देगी, जिसका विस्तार 14 मॉडलों तक होगा.

जबरदस्त माइलेज

मारुति सुजुकी 26.6 किमी प्रति किलोग्राम सीएनजी की अधिकतम फ्यूल एफिसिएंशी का दावा करती है, जो इसे लगभग स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन के रूप में किफायती बनाती है. सीएनजी पावर्ड वर्जन के आगमन के साथ, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा अब तीन वर्जन में उपलब्ध है – शुद्ध पेट्रोल, मजबूत पेट्रोल हाइब्रिड और सीएनजी. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सीएनजी के लॉन्च के बाद टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर सीएनजी होगी, जिसमें पहले की तरह ही पावरट्रेन होगा और आधिकारिक तौर पर ऑटो एक्सपो 2023 में लॉन्च होने की उम्मीद है.

बदलेगा कार चलाने का तरीका! AI और रोबोटिक्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी से लैस हैं कारें, इस दिन

नई दिल्ली. हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने 2023 ऑटो एक्सपो के लिए अपनी लाइन-अप की घोषणा की है. दक्षिण कोरियाई कंपनी इस साल 'बियॉन्ड मोबिलिटी वर्ल्ड' थीम पर कारों का निर्माण करेगी. कंपनी पहले ही पुष्टि कर चुकी है कि Ioniq 5 को एक्सपो में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ऑटोमेकर की योजना Ioniq 6 इलेक्ट्रिक सेडान, नेक्सो फ्यूल सेल EV के साथ-साथ नई ADAS टेक्नोलॉजी को भी दिखाने की है.

2023 ऑटो एक्सपो में हुंडई पवेलियन को फ्यूचर मोबिलिटी के कई पहलुओं को प्रदर्शित करने वाले कई क्षेत्रों में बांटा जाएगा. इसमें क्लीन मोबिलिटी जोन शामिल है, जिसमें Ioniq 6 और Nexo फ्यूल-सेल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे. दोनों मॉडल जीरो एमिशन मोबिलिटी और बाजार में पर्यावरण के अनुकूल समाधान लाने के हुंडई के मकसद को दिखाते हैं.

E-GMP प्लेटफॉर्म पर बनी हैं कारें

Hyundai Ioniq 6 और Ioniq 6 दोनों ही वाहन निर्माता के E-GMP (इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म) पर बने हैं, जो इस क्षेत्र में भी प्रमुख भूमिका निभाएगा. इस जोन में Ioniq 5 की V2L टेक्नोलॉजी, फास्ट चार्जिंग, कस्टमाइजेबल सीटिंग और रिलैक्सेशन सीट को भी दिखाया जाएगा.

भविष्य में कैसी होगी सेफ्टी?

ADAS जोन एक अन्य प्रमुख अट्रैक्शन होगा, जो वर्चुअल रियलिटी (VR) और गेमिंग के जरिए से Hyundai SmartSense या Level 2 ADAS तकनीक का प्रदर्शन करेगा. लेवल-2 ADas नई पीढ़ी के टक्सन में पहले से ही उपलब्ध है और संभावना है कि सेफ्टी सिस्टम इस साल के आखिर में आने वाली क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल में भी देखने को मिल जाएगा.

मेटावर्स में भविष्ट का एक्सपीरियंस कर सकेंगे

कंपनी अपनी हुंडई मोबिलिटी एडवेंचर के साथ Roblox Metaverse में भी एंटर करेगी, जो एक ज्यादा इमर्सिव ब्रांड एक्सपीरियंस के लिए एक वर्चुअल सेट-अप लाएगा. मारुति सुजुकी पहले ही अपनी कारों के लिए मेटावर्स में प्रवेश कर चुकी है और हुंडई भी लीग में शामिल हो जाएगी. विजिटर कंपनी के पवेलियन में हुंडई मेटावर्स का अनुभव कर सकेंगे.

कई नई टेक्नोलॉजी का होगा प्रदर्शन

हुंडई पवेलियन में मोबिलिटी जोन में ATLAS, H-MEX और MobED जैसे फ्यूचर रोबोट का प्रदर्शन भी किया जाएगा. इनमें AI और रोबोटिक्स पर आधारित कई तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा. बोस्टन डायनेमिक द्वारा SPOT मोबाइल रोबोट भी इस कार्यक्रम में प्रदर्शित किया जाएगा. कंपनी भविष्य के तकनीकी इनोवेशन पर अर्बन एयर मोबिलिटी और पर्पज बिल्ड व्हीकल को प्रदर्शित करने के लिए एक स्केल मॉडल के साथ अपनी कनेक्टेड कार तकनीक का भी प्रदर्शन करेगी.

इनसाइड

इलेक्ट्रिक ट्रक बाजार में स्पीड की 'रेस', पिकअप पर जोर दे रहीं कंपनियां, फोर्ड-टेस्ला को मिलेगी RAM से टक्कर

नईदिल्ली. इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती मांग के बीच अब कंपनियों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है. यही कारण है कि कंपनियां अब हर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च कर रही है. फोर्ड बाजार में अपना इलेक्ट्रिक पिकअप (Ford Electric Truck) ट्रक उतार चुकी है. वहीं, टेस्ला का इलेक्ट्रिक ट्रक (Tesla Electric Truck) इस साल मार्केट में आने की उम्मीद है. इन दोनों ही कंपनियों को टक्कर देने के लिए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आटोमोबाइल निर्माता स्टेलेंटिस भी इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक बाजार में उतारेगा. स्टेलेंटिस ने राम (RAM pickup electric truck) ब्रांड नेम से बनाए अपने पिकअप ट्रक की झलक लॉस वेगॉस में हो रहे 2023 कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स शो में दिखाई है. हालांकि, कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है.

जानकारों का मानना है कि स्टेलेंटिस का इलेक्ट्रिक ट्रक फोर्ड और टेस्ला के ट्रक्स को पूरी टक्कर देगा और इसमें कुछ खास फीचर्स हो सकते हैं. इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक के मामले में स्टेलेंटिस अन्य कंपनियों से अभी पीछे है. कंपनी ने इस दिशा में देरी से कदम उठाया है. लेकिन, अब कंपनी पूरी ताकत से जुट गई है.

2024 से उत्पादन शुरू

राम ब्रांड के हेड, माइक कोवाल ने कहा कि ट्रक खरीददारों की पेलोड, टोइंग और चार्जिंग जैसी मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे राम 1,500 रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक (Ram 1500 Revolution electric pickup truck) में कई खूबियां होंगी, जो इसे दूसरों से अलग करेगी. हालांकि कोवाल ने इसकी कीमत और अन्य फीचर्स के बारे में कुछ भी बताने से इंकार कर दिया. वेगास में प्रदर्शित किया गया प्रोटोटाइप में 18 फुट लंबा स्टोरेज स्पेस, रिमुवेबल जंम सीट और एआई पावर्ड शैडो मोड दिया गया है. शैडो मोड की सहायता से ट्रक को बाहर से भी वाइस कमांड देकर संचालित किया जा सकता है.

फोर्ड ने उतारा Ford F-150 Lightning

फोर्ड ने अमेरिकी बाजार में Ford F-150 Lightning पिक-अप ट्रक उतारा है. F-150 Lightning को तीन वेरिएंट्स में बनाया है. इसकी कीमत लगभग 29 लाख रुपये है. F-150 Lightning में 563 हॉर्सपावर और 775 पाउंड-फीट का टॉर्क दिया गया है. 0 से 100 की गति यह 4 सेकेंड में पकड़ लेता है.

टेस्ला भी लाएगी इलेक्ट्रिक ट्रक

टेस्ला साइबरट्रक (Tesla Cybertruck) नाम से अपना इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. सबकुछ ठीक रहा तो इस साल इसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है. इस पिकअप ट्रक को 3 तरह के मोटर ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है, जिसमें सिंगल मोटर आरडब्ल्ययूडी की बैटरी रेंज 250 मील यानी 400 किलोमीटर से ज्यादा होगी.

ऑटो इंडस्ट्री हुई काफी एडवांस, हाइड्रोजन से लेकर फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां आईं नजर

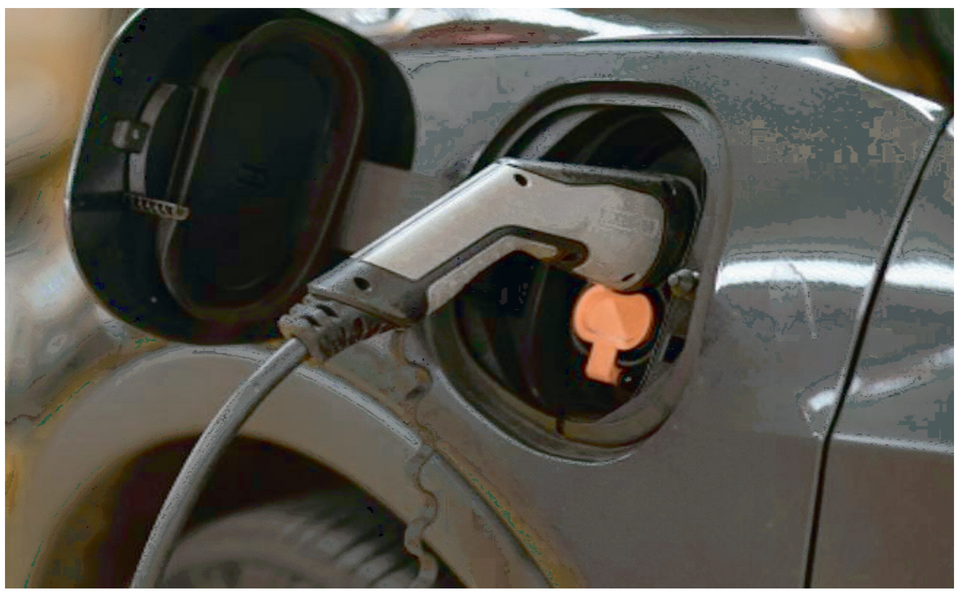

साल 2022 में जितने भी गाड़ियां लांच हुई है उनमें से अधिकतर गाड़ियों में या तो लेवल वन या फिर level-2 एडवांस फीचर दिया गया है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Advanced Driver Assistance Systems) यह एक टॉप क्लास मेकैनिज्म है।

नई दिल्ली। साल 2022 ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहद ख़ास रहा है क्योंकि, कोरोना के प्रभाव से पूरी इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी या वह साल है जहां पर कंपनी ने अच्छी खासी ही है। 2022 में ऑटो इंडस्ट्री के अंदर कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिसको हम आधुनिकीकरण के तौर पर देखते हैं।

हाई-टेक एक्सप्रेसवे-

साल 2022 में देश को पहला हाई-टेक एक्सप्रेस वे मिला, जहां 11 दिसंबर से 701 किलोमीटर लंबा मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस एक्सप्रेस वे पर कई ऐसी एडवांस सुविधाएं दी गई हैं, जो शायद ही किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलेंगी।

हाइड्रोजन कार-

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस साल हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को प्रमोट करते हुए देखा गया है। दरअसल, ईंधन के विकल्प के तौर र हाइड्रोजन कार को देश के फ्यूचर के तौर पर देखा जा रहा है।

ADAS फीचर-

साल 2022 में जितने भी गाड़ियां लांच हुई है उनमें से अधिकतर गाड़ियों में या तो लेवल वन या फिर level-2 एडवांस फीचर दिया गया है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Advanced Driver Assistance Systems) यह एक टॉप क्लास मेकैनिज्म है। यह आपको ऑटोमैटिक कार वाली फीलिंग देता है। यह किसी जर्मन या अमेरिकी गाड़ी में नहीं, बल्कि भारत में बनी महिंद्रा की कारों में भी देखने को मिलता है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Advanced Driver Assistance Systems) बहुत ही खास सेफ्टी फीचर है, जो आपको सुरक्षित रखने में हेल्प करता है। यह सिस्टम आगे चलने वाली गाड़ी से एक समान दूरी मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है।

फ्लेक्स फ्यूल कार-

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2022 में टोयोटा मिराई नाम की फ्लैक्स फ्यूल कार को भारत में लांच किया था । यह गाड़ी देश की पहली फ्लाइट स्कूल पर चलने वाली कार थी अभी हाल ही में मारुति ने वैगनआर को फ्लेक्स टूल कांसेप्ट को अनवील किया था।

इलेक्ट्रिक वाहन-

इलेक्ट्रिक वाहन का चलन दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। इस साल कई बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों ने अपने अपने वाहनों को लॉन्च किया है। आने वाले दिनो में इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों के कारण हर कोई इलेक्ट्रिक वाहन को अपना रहा है। लोगों का तेजी से अनना इसके भविष्य को दर्शाता है।

फास्ट चार्जर-

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से बढ़ते जा रही है। लोग इसको अपना भी तेजी से रहे हैं लेकिन आज भी लोगों के दिलो में इसको लेकर एक सवाल रहता है चार्जिंग स्टेशन और फास्ट चार्जर। समय काफी तेजी से भागता है लोग इस समय हर चीज बिना समय गवाए पाना चाहते हैं। इसी को देखते हुए सरकार काफी तेजी से ईवी चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित कर रही है। इसके साथ ही इतने ही तेजी से वाहन निर्माता कंपनियां फास्ट चार्जर को बनाने में जोर दे रही है ताकि लोग बिना समय गवाए अपनी कार को तेजी से चार्ज कर सके।

पाकिस्तान में टीटीपी की दहशत

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे किसी दिन स्वयं उसमें गिरते हैं। लगता है पाकिस्तान में यह कहावत सच सिद्ध हो रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार स्थापित करने में मदद की थी। उसे लगता था कि अफगानिस्तान में भारत विरोधी सरकार बन जाएगी जिससे पाकिस्तान को लाभ हो।

टीटीपी की शर्त थी कि पाकिस्तान सरकार ट्रायबल क्षेत्र उसके हवाले कर दे। इसका मतलब था कि पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनखवा पर अपना दावा छोड़ कर उसे टीटीपी के हवाले कर दे। बातचीत फेल हुई तो टीटीपी के हमले भी तेज हो गए। ये हमले पाकिस्तान में ही तेज नहीं हुए बल्कि अफगानिस्तान में भी पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले हुए। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर हमला इतना भयंकर था कि पाकिस्तानी राजदूत किस्मत से ही बच पाया। काबुल का कहना है कि यह हमला इस्लामी स्टेट ख़ुरासान के लोगों ने किया जबकि इस्लामाबाद का आरोप है कि टीटीपी और आईएस के लोग आपस में मिले हुए हैं। पिछले दिनों तो टीटीपी ने पाकिस्तान के सिविल समाज को भी हिला दिया। उन्होंने कहा कि टीटीपी पाकिस्तान की सत्ता पर उसी प्रकार कब्जा कर लेगी जिस प्रकार तालिबान ने अमेरिका को भगा कर काबुल पर कब्जा कर लिया था। उसने बाकायदा सरकार के मंत्रालयों की और मंत्रियों की घोषणा कर दी जिनको इस्लामाबाद पर कब्जा करने के बाद दायित्व दिया जाएगा। पाकिस्तान सरकार को लगा कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार तो उसने ही स्थापित की है'

एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे किसी दिन स्वयं उसमें गिरते हैं। लगता है पाकिस्तान में यह कहावत सच सिद्ध हो रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार स्थापित करने में मदद की थी। उसे लगता था कि अफगानिस्तान में भारत विरोधी सरकार बन जाएगी जिससे पाकिस्तान को लाभ हो। अमेरिका अफगानिस्तान में बुरी तरह फंस गया था। वह वहां से किसी तरह निकलना चाहता था। इसके लिए वह तालिबान तक को काबुल सौंपने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस काम के लिए उसे जिस मध्यस्थ की जरत थी, वह भूमिका पाकिस्तान ने निभाई। जाहिर है वह इस मामले में अमेरिका के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुआ। इसे भी वह भारत विरोध में ही भुनाना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान इस पूरी रणनीति में एक महत्वपूर्ण तथ्य को भूल गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली डूरंड लाईन को अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान शासित अफगानिस्तान डूरंड लाईन को स्वीकार कर लेगा। उसका कारण भी था। तालिबान भी इस्लाम को प्रमुखता देता है और पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पर था। इसलिए पाकिस्तान समझ रहा था कि इस्लाम दोनों देशों के सम्बन्धों को और मज़बूत करने का काम करेगा। लेकिन वह भूल गया कि जो इस्लाम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को ही एक नहीं रख पाया वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कैसे जोड़ देगा? लेकिन दोनों देशों में ऐसा क्या विवाद है जिसने इस्लाम को भी दोयम दर्जे में ला दिया है। जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है डूरंड रेखा के दोनों ओर पश्तून रहते हैं। उनके लिए यह सीमा रेखा कोई मायने नहीं रखती। वे दोनों ओर आते-जाते रहते हैं। उनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं। पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनखवा मोटे तौर पर पश्तूनों या पठानों का सूबा है। पश्तून पाकिस्तान से उसी तरह आज़ाद होना चाहते हैं जिस प्रकार कभी बंगाली पाकिस्तान से निकल जाना चाहते थे।

पाकिस्तान से अलग होने के लिए पश्तूनों ने टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम का संगठन बनाया हुआ है। यह संगठन अहिंसा में विश्वास नहीं रखता। वह पाकिस्तान से उसी तरीक़े से आजादी प्राप्त करना चाहते हैं जिस प्रकार कभी अफगानिस्तान के तालिबान अमेरिका से प्राप्त करना चाहते थे। यानी बम और बन्दूक के माध्यम से। इतना तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के पश्तून इलाक़ों में और चीज़ों की कमी हो सकती है लेकिन हथियारों की कमी नहीं है। टीटीपी के कार्यकर्ता पाकिस्तान सेना के ठिकानों पर हमला करके अफगानिस्तान में चले जाते हैं। टीटीपी ने बलूची आजादी के लिए संघर्ष कर रहे बलोच योद्धाओं से भी हाथ मिला लिया है। माना जाता है कि पिछले साल बलूचिस्तान और पख्तूनखवा में टीटीपी के हमलों में 44 फीसदी वृद्धि हुई है। यहां तक कि इस्लामाबाद में भी हमले हुए। पिछले कुछ दिनों से अफगनिस्तान सरकार टीटीपी और पाकिस्तान सरकार में समझौता करवाने की कोशिश कर रही थी। इस कारण से टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच एक प्रकार से युद्ध विराम की स्थिति बना हुई थी। लेकिन यह बातचीत कुछ दिन पहले असफल हो गई। टीटीपी की शर्त थी कि पाकिस्तान सरकार ट्रायबल क्षेत्र उसके हवाले कर दे। इसका मतलब था कि पाकिस्तान सरकार खैबर पख्तूनखवा पर अपना दावा छोड़ कर उसे टीटीपी के हवाले कर दे। बातचीत फेल हुई तो टीटीपी के हमले भी तेज हो गए। ये हमले पाकिस्तान में ही तेज नहीं हुए बल्कि अफगानिस्तान में भी पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले हुए। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर हमला इतना भयंकर था कि पाकिस्तानी राजदूत क़िस्मत से ही बच पाया। काबुल का कहना है कि यह हमला इस्लामी स्टेट ख़ुरासान के लोगों ने किया जबकि इस्लामाबाद का आरोप है कि टीटीपी और आईएस के लोग आपस में मिले हुए हैं। पिछले दिनों तो टीटीपी ने पाकिस्तान के सिविल समाज को भी हिला दिया। उन्होंने कहा कि टीटीपी पाकिस्तान की सत्ता पर उसी प्रकार कब्जा कर लेगी जिस प्रकार तालिबान ने अमेरिका को भगा कर काबुल पर कब्जा कर लिया था।

उसने बाकायदा सरकार के मंत्रालयों की और मंत्रियों की घोषणा कर दी जिनको इस्लामाबाद पर कब्जा करने के बाद दायित्व दिया जाएगा। पाकिस्तान सरकार को लगा कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार तो उसने ही स्थापित की है। इसलिए उसे थोड़ा डांटना चाहिए कि पाकिस्तान के तालिबान की सहायता न करे। यदि वह यहीं तक सीमित रहती तब शायद मामला इतना न उलझता और बात छिपी रहती। लेकिन पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इस्लामी भाई होने के नाते हम पहले तो अफगानिस्तान से आग्रह करेंगे कि पाकिस्तानी तालिबान को हमारे हवाले कर दें, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता और ऐसा हो भी नहीं रहा है तो पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान के भीतर घुस कर पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी के ठिकानों को नष्ट करेगी। पाकिस्तान के इस बड़बोलेपन का उत्तर तुरंत अफगानिस्तान के तालिबान प्रतिनिधि जबीउल्लाह मुजाहिद ने दिया। उसने कहा कि पाकिस्तान इस प्रकार की हरकत के बारे में सोचने की भी गलती न करे। काबुल अपने देश की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। वह किसी देश को भी अपने देश में दखलअंदाजी की अनुमति नहीं देगा। वह सभी पड़ोसी देशों से शान्तिपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहता है। जहां तक पाकिस्तान की सेना की बहादुरी का प्रश्न है, उसका उत्तर जबीउल्लाह ने वह तस्वीर सांझा करके दिया जिसमें 1971 में पाकिस्तानी सेना भारत के आगे 90000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर रही थी। जाहिर है पाकिस्तान उसी चक्रव्यूह में ख़ुद फंस गया है जो उसने कभी भारत को घेरने के लिए रचा था। भारत में इस स्थिति को पाकिस्तान के लिए शर्मनाक माना जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा ही भारत के खिलाफ आतंकवाद का प्रयोग करता रहा है। ऐसी स्थिति में भारत का खुश होना स्वाभाविक है। अब देखते हैं कि पाक की क्या प्रतिक्रिया रहती है।

संपादक की कलम से

राहुल प्रशंसक संघ-संत

आरएसएस से जुड़े प्रमुख चेहरे और अयोध्या राम जन्मभूमि के साधु-संतों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' की न केवल प्रशंसा की है, बल्कि प्रभु रामलला के आशीर्वाद की शुभकामनाएं भी दी हैं। संघ-संतों की इस जमात में सबसे प्रमुख हैं-चंपत राय। वह श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव हैं। यूं कहें कि अयोध्या में निर्माणाधीन प्रभु राम के भव्य मंदिर के बुनियादी कर्ताधर्ताओं में एक हैं। चंपत राय आरएसएस से जुड़े रहे हैं। उनकी टिप्पणी गौरतलब है कि इतनी सर्दी में 50 साल का एक नौजवान पैदल चल रहा है, यह वाकई प्रशंसनीय है। राहुल गांधी यात्रा कर देश को समझना चाहते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठंड के मौसम में 3000 किलोमीटर चलना बड़ी बात है। उनकी यात्रा की न तो संघ ने और न ही प्रधानमंत्री ने आलोचना की है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येन्द्र दास के अलावा महंत दिव्य कला, महंत जनमेजय शरण, महंत करुणानिधान, महंत मैथिली रमण आदि ने भी श्रीराम के आधार पर राहुल गांधी को आशीर्वाद दिए हैं और उनके स्वास्थ्य, दीर्घायु की मंगलकामना भी की है। ये सभी आध्यात्मिक चेहरे अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े हैं। न जाने किस संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस नेता को आशीर्वाद और प्रशंसा की शुभकामनाएं दी हैं! ये शब्द और आशीष एकदम राजनीतिक भी नहीं हो सकते, क्योंकि संघ ऐसी राजनीतिक टिप्पणियों से दूर ही रहा है और साधु-संतों का सियासत से क्या सरोकार हो सकता है? यह जरूर कहा और माना जा सकता है कि ऐसे हिन्दूवादी और राममय चेहरे कोई ओछी टिप्पणी भी नहीं करते। इन आशीर्वचनों में लक्षणा-व्यंजना अथवा किसी प्रकार के तंज को तलाशना भी गलत होगा। ये आशीर्वाद निश्छल और स्वाभाविक हैं, आत्मा की गहराइयों से दिए गए हैं। ऐसी मंगलकामनाओं से राहुल गांधी 'रामभक्त' हो जाएंगे या उनकी नफरती भाषा, ज़हरीली सोच बदल जाएगी अथवा राजनीतिक समीकरणों में एक और पार्टी 'राममय' हो जाएगी, हम इतनी जल्दी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने वाले नहीं हैं। अलबत्ता यह एक बेहद सकारात्मक और सुकूनदेय प्रतिक्रिया है, जो प्रथमदृष्ट्या साबित करती है कि संघ को नफरत और तोडने, विभाजित करने वाला संगठन करार देना और बार-बार उस पर लांछन लगाने की राजनीति भी दुराग्रही है। राहुल गांधी भी कमोबेश इसी राजनीतिक सोच के शिकार रहे हैं। संघ नेता और साधु-संतों का आशीष भरा व्यवहार राहुल को सोचने पर बाध्य कर सकता है। सवाल यह भी उभरा है कि संघ और संतों का कुछ हृदय-परिवर्तन हुआ है अथवा ये आशीर्वाद और प्रशंसाएं भी किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं? राहुल गांधी की यात्रा अभी उप्र को पार कर हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। उप्र के दौरान यात्रा अयोध्या के करीब भी नहीं आई। बागपत, शामली, कैराना आदि के जाटबहुल, मुस्लिमवादी और दलितवादी इलाकों से यात्रा गुज़र कर गई है। उप्र प्रवास के दौरान अयोध्या राम मंदिर का कोई मुद्दा भी नहीं उभरा था। फिर भी संघ और संतों ने यात्रा की प्रशंसा की है।

महंत सत्येन्द्र दास ने तो राहुल गांधी को पत्र तक लिखा है। राहुल देश को टूटा हुआ मानकर उसे जोडने के प्रयास में निकले हैं, जबकि संघ 'अखंड भारत' की बात करता रहा है और हम भी इसी सोच के पक्षधर हैं कि भारत एक विविध और संगठित राष्ट्र है। दरअसल यह यात्रा कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी को व्यस्त रखने की जन-संपर्क कवायद है, ताकि देश में उनकी छवि एक परिपक्व नेता की बनाई जा सके। सवालिया तो यह भी है कि उप्र में यात्रा के दौरान मायावती, अखिलेश यादव और ओमप्रकाश राजभर सरीखे प्रमुख विपक्षी नेता शामिल क्यों नहीं हुए?

07 जनवरी का इतिहास

2020 – नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने भुगतान तेज और सुरक्षित करने के लिए वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मंच ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है।

ईरान की संसद ने एक विधेयक पारित कर सभी अमेरिकी बलों को आतंकवादी घोषित कर दिया।

रवींद्र नाथ महतो को सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक 'कर्मयोद्धा ग्रंथ' का विमोचन किया।

केंद्र सरकार ने कई मीडिया घरानों को पहला 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान' प्रदान किया। इस सम्मान का उद्देश य योग के संदेश के प्रसार में मीडिया के योगदान को रेखांकित करना है।

2015 – पेरिस में दो बंदूकधारियों ने 'चार्ली आब्दो' पत्रिका के कार्यालय पर हमला किया जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य लोग घायल हो गए।

यमन की राजधानी सना में एक पुलिस कॉलेज के बाहर हुए कार बम धमाके में 38 लोगों की मौत और 63 से अधिक लोग घायल।

2010 – जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर एक होटल में छिपे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगभग 22 घंटे लंबी मुठभेड़ दो आतंकवादियों के मारे जाने के साथ ख़त्म हो गयी।

2009 – आई टी कम्पनी सत्यम के चेयरमैन रामालिंगम राजू ने अपेन पद से इस्तीफ़ा दिया।

2008 –
राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने विनोद राय को नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की शपथ दिलाई। भारत व मलेशिया वायुसेना के पायलटों और युद्धपोतों के कर्मियों के प्रशिक्षण समेत रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

जार्जिया में नेल मिखै साकाश विली को पुनः देश का राष्ट्रपति चुना गया।

2003 – जापान ने विकास कार्यों में मदद के लिए भारत को 90 करोड़ डालर की मदद की घोषणा की।

2000 – जकार्ता (इंडोनेशिया) में 10 हज़ार मुसलमानों ने मोलुकस द्वीप समूह में ईसाईयों के विरुद्ध जेहाद की घोषणा की।

1999 – अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाही शुरू।

1989 – जापान के सम्राट हिरोहितो का देहावसान, आकिहितो नये सम्राट घोषित।

1987 – कपिल देव ने टेस्ट क्रिकेट में तीन सौ विकेट पूरे किये।

1980 – भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी।

1972 – स्पेन के इबीसा क्षेत्र में विमान दुर्घटना में चालक दल के छह सदस्यों समेत 108 यात्रियों की मौत।

1959 – संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की नई सरकार को मान्यता प्रदान की।

1953 – अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम बनाने की घोषणा की।

नेताओं की बदजुबानी कैसे रोकी जाये? यह प्रश्न अब भी बरकरार है

शेष चारों जजों का कहना था कि संविधान कहता है कि देश में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता का जो भी दुरुपयोग करेगा, उसे सजा मिलेगी। ऐसी स्थिति में अलग से कोई कानून थोपना तो अभिव्यक्ति की इस स्वतंत्रता का हनन होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है कि कोई मंत्री यदि आपत्तिजनक बयान दे दे तो क्या उसके लिए उसकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? यह मुद्दा इसलिए उठा था कि आजम खान नामक उत्तर प्रदेश के मंत्री ने 2016 में एक बलात्कार के मामले में काफी आपत्तिजनक बयान दे दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों में से चार की राय थी कि हर मंत्री अपने बयान के लिए खुद जिम्मेदार है। उसके लिए उसकी सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस राय से अलग हटकर न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न का कहना था कि यदि उस मंत्री का बयान किसी सरकारी नीति के मामले में हो तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाली जानी चाहिए।

शेष चारों जजों का कहना था कि संविधान कहता है कि देश में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता का जो भी दुरुपयोग करेगा, उसे सजा मिलेगी। ऐसी स्थिति में अलग से कोई कानून थोपना तो अभिव्यक्ति की इस स्वतंत्रता का हनन होगा। संविधान की धारा 19 (2) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो भी मर्यादाएं रखी गई हैं, वे पर्याप्त हैं। चारों न्यायाधीशों की राय काफी तर्कसंगत प्रतीत होती है लेकिन जज नागरत्न की चिंता भी ध्यान देने लायक है। आखिर मंत्री का बयान प्रचारित इसलिए होता है कि वह मंत्री है। वह सरकार का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन उसके व्यक्तिगत बयानों के लिए सरकार को जिम्मेदार कैठे ठहराया जा सकता है?

इसके अलावा यह तय करना भी आसान नहीं है कि उसका कौन-सा बयान व्यक्तिगत है और कौन-सा उसकी सरकार से संबंधित है। मैं सोचता हूं कि इस मामले में जैसा कानून अभी उपलब्ध है, वह पर्याप्त है। कानून की नई सख्तियाँ लागू करने से भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे मंत्री और नेता लोग खुद पर ज़रा आत्म-संयम लागू करें। उनका मंत्रिमंडल और उनकी पार्टी उन्हें मर्यादा में रहना सिखाए। दुखद स्थिति यह है कि पार्टी और सरकार के सर्वोच्च नेता भी अनाप-शनाप बयान देने से बाज नहीं आते। अखबार और टीवी चैनल भी उन जहरीले चटपटे बयानों को उछालने का मजा लेते हैं। यदि हमारी खबरपालिका अपनी लक्ष्मण-रेखाएँ खींच दे तो इस तरह के जहरीले, कटुतापूर्ण और घटिया बयानों पर किसी का ध्यान जाएगा ही नहीं। जो नेतागण इस तरह के बयान देने के आदी हैं, उनकी पार्टी उन पर कड़े प्रतिबंध भी लगा सकती हैं, उन्हें दंडित भी कर सकती हैं। यदि हमारी खबरपालिका और पार्टियां संकल्प कर लें तो वे नेतागण की इस बदजुबानी को काफी हद तक रोक सकती हैं। अदालतों के सहारे उन्हें रुकवाने से यह कहीं बेहतर तरीका है।

-डॉ. वेदप्रताप वैदिक

सरकार के पालने में

मुख्यमंत्री का सामाजिक व सांस्कृतिक चेहरा जब दर्द का एहसास करे, तो सामान्य नीतियों की पड़ताल भी अंतिम पायदान तक स्पर्श करती है। एक पालक मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू का छह हजार अनाथों के प्रति संवेदनशील होना, दर्शाता है कि वह सरकार को सामान्य फर्ज अदायगी से कहीं आगे ले जाना चाहते हैं। अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए 101 करोड़ से शुरू किया जा रहा 'सुखाश्रय' कोष, अपने साथ वचनबद्धता के अनूठे प्रतीकों की संरचना भी कर रहा है। विधायकों के पहले वेतन से निकल रहा एक-एक लाख रुपए का योगदान, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जनप्रतिनिधियों का रवैया जरूर बदलेगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले धन आबंटन की परंपराएं कम या कमजोर रहीं, लेकिन विभागीय रूटीन में सरोकारों की कमी हमेशा दिखाई देती रही है। मुख्यमंत्री राहत कोष का इस्तेमाल सदा नजराने के रूप में होता आया है और इसके तहत लाभार्थी दरअसल राजनीतिक आपूर्तियों की दृष्टि से चुने जाते रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां प्रदेश भर में अपने कारनामें करती रही हैं या आंकड़ों की दृष्टि में आगे बढ़ती रही हैं, लेकिन यहां एक ऐसी शुरुआत हो रही है जिसका संबंध 'एक नए मिशन' के धरातल को पुख्ता कर रहा है। सबसे अहम बात यह कि समाज की दृष्टि में 'अनाथ बच्चों' का भविष्य सुनिश्चित होगा। बहरहाल यह कदम केवल एक सीमित उद्देश्य की आपूर्ति नहीं, बल्कि ऐसे कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने की नई दृष्टि भी है। 'सुखाश्रय कोष' के जरिए व्यवस्थागत जरूरतों के अलावा लक्ष्य केंद्रित इंसाफ दिलाने की इस मुहिम को जनता का समर्थन मिले, तो हर नागरिक के पास एक ऐसा अवसर है जहां कुछ न कुछ समाज को लौटाया जा सकता है। यह इसलिए भी कि समाज अपने दायित्व की मूल भावना से दूर हटकर केवल दर्शक बनता जा रहा है।

जहां वृद्धाश्रम अब समय की जरूरत बन रहे हों, वहां समाज की आपाधापी में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी होता जा रहा है। बेशक सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में ऐसे संस्थानों की संख्या निरंतर बढ़ी है, लेकिन इनके संचालन में सेवा भावना का अभाव हमेशा दुखदायी बना रहा। बीच-बीच में कुछ घटनाओं के कारण अनेक प्रश्न खड़े होते रहे हैं, जिन्हें केवल कानून की दृष्टि से देखकर पूर्ण सुधार नहीं हुआ, अतः नए सिरे से ऐसी सभी संस्थाओं का निरीक्षण-परीक्षण करना होगा तथा सारी व्यवस्था को फिर से लिखना पड़ेगा। सरकार अकेले धन की व्यवस्था तो मुकम्मल कर सकती है, लेकिन इनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समाज का योगदान अपरिहार्य है। बहरहाल सुक्खू सरकार ने अपने आरंभिक निर्णयों में से एक यानी 'सुखाश्रय कोष' के मार्फत यह संदेश तो दिया ही है कि अगर नेक नीयत से शुरुआत की जाए तो अवश्य ही समाज का समर्थन भी मिल सकता है।

सरकार के पालने में समाज की अनेक पीड़ाएं अगर राहत की डोर प्राप्त कर लें, तो सत्ता में होने की दृष्टि का आभास भी होगा। प्रशासनिक रूटीन और सरकारी आंकड़ों की मशीन से इतर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू अपने लिए नए टारगेट सामने रखकर चल रहे हैं। ये उन्हें एक अलग कतार में खड़ा होने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। कहीं कड़े निर्णय, तो कहीं मार्मिक संदेश उनके व्यक्तित्व को अलग-अलग पहलुओं में देख रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री जैसा वह सोच रहे हैं, उसे अगर हर जन प्रतिनिधि के मार्फत अमल में ला पाएं तो ऐसे हर कार्य का अंजाम भी इसी तरह प्रतिष्ठित होगा। अब तक के मानदंडों, कार्यप्रणाली, योजनाओं के कार्यान्वयन तथा लक्ष्यों की कसौटियों में प्रायः यह देखा जाता रहा है कि उच्च प्राथमिकताएं तथा उदार लक्ष्य प्रशासन-शासन निचली तहों में आकर फंस जाते हैं और अगर मुख्यमंत्री ऐसी आशंकाओं को निरस्त कर पाए, तो निश्चित रूप से उनके प्रशंसक बढ़ जाएंगे।

हल्द्वानी प्रोटेस्ट के स्वरूप ने साबित किया- 'शाहीन बाग' संयोग नहीं प्रयोग था...

नीरज कुमार दुबे

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी में बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए ढांचों को गिराने के आदेश दिए थे। न्यायालय ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स की मदद ले।

अवैध कॉलोनियों से जब भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है तो उसे सियासी लोग धार्मिक रंग देने का काम करते हैं। दिल्ली में पिछले साल एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग समेत कई अन्य इलाकों में पहुँचा तो इस कार्रवाई को एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ अभियान करार दिया गया। अब उत्तराखंड चर्चा में है क्योंकि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी से कब्जा हटाने का जो आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिया है उसके खिलाफ सियासत शुरू हो गयी है। एकदम शाहीन बाग के आंदोलन की तर्ज पर महिलाओं और बच्चों को ठंड के मौसम में आगे कर प्रदर्शन करवाया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। यहाँ हमें समझना होगा कि सरकारी जमीन सार्वजनिक संपत्ति होती है किसी एक की बपौती नहीं। सरकारी जमीन से कब्जा छुड़वाने के प्रयास को अन्याय का रूप देना गलत है। देश संविधान से चलता है ना कि भावनात्मक या धार्मिक आधार पर। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है तो नेताओं को बड़बोले बयान देने की बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए। वैसे हल्द्वानी में आंदोलन का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है उससे एक बात साबित हो गयी है कि शाहीन बाग कोई संयोग नहीं बल्कि प्रयोग था जोकि अब जगह-जगह दोहराया जा रहा है।

जहां तक हल्द्वानी मामले की बात है तो आपको बता दें कि अवैध कॉलोनी बताये जा रहे बनभूलपुरा के पांच हजार से ज्यादा घरों पर संकट मंडराने लगा है क्योंकि रेलवे ने अपनी जमीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए जो याचिका दायर की थी उस पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जमीन खाली कराने के निर्देश दिये हैं। इसके बाद सियासत ऐसी शुरू हो गयी है कि इस पहाड़ी राज्य के नेताओं से लेकर हैदराबाद के ओवैसी तक इस मामले में कूद गये हैं। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच चुका है और पांच जनवरी को इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका स्थानीय निवासियों के साथ हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक ने दाखिल की है। उनके वकील सलमान खुर्शीद हैं। दूसरी याचिका वकील प्रशांत भूषण ने दाखिल की है। रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा सुनवाई करेंगे।

हम आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी में बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए ढांचों को गिराने के आदेश दिए थे। न्यायालय ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स की मदद ले, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाए। इसके बाद जगह खाली करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों की मदद से नोटिस दिये गये। जिसके बाद हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में क्षेत्र के निवासियों ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इलाके के लोगों का कहना है कि वे लोग इस क्षेत्र में 70 साल से रह रहे हैं। वहां 20 मस्जिदें, 9 मंदिर, पानी की टंकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1970 में डाली गई एक सीवर लाइन, दो इंटर कॉलेज और एक प्राथमिक विद्यालय है इसलिए यह क्षेत्र अवैध कब्जे वाला नहीं है। इलाके के लोगों का कहना है कि हम प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वे इस तथा-कथित अतिक्रमण को हटाने पर मानवीय पहलू से विचार करें। इलाके के लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर यह रेलवे की जमीन थी तो सरकार ने इसे पट्टे पर कैसे दिया था? इस मामले में क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा, "करीब सौ साल से इस क्षेत्र में लोग बसे हुए हैं। यहां 70 साल पुरानी मस्जिदें और मंदिर हैं। यहां नजूल जमीन, पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और लीजधारक हैं।" उन्होंने कहा, "रेलवे जिस 78 एकड़ जमीन को अपना बताता है, उसे खाली करने का विरोध करने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय गये। हम उच्चतम न्यायालय भी गये जहां हमारे वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद मामले की पैरवी कर रहे हैं लेकिन जिस सरकार ने जमीन पर स्कूल एवं अस्पताल बनवाये, उसने अपने नागरिकों की कोई परवाह नहीं की।'' विधानसभा में हल्द्वानी सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे सुमित हृदयेश ने हाल में प्रदर्शनकारियों के धरने में भी हिस्सा लिया था। हम आपको बता दें कि यह सीट पारंपरिक रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं उनकी मां इंदिरा हृदयेश जीतती थीं।

जहां तक इस पूरे मामले का सवाल है तो आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायायल ने हल्द्वानी के इस इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का 20 दिसंबर को आदेश दिया था। न्यायालय ने अतिक्रमणकर्ताओं को वह जगह खाली करने के लिए एक हफ्ते का नोटिस देने का आदेश दिया था। हालांकि बनफूलपुरा के हजारों बाशिंदों ने अतिक्रमण हटाने का यह कहते हुए विरोध किया कि वे बेघर हो जायेंगे और स्कूल जाने वाले उनके बच्चों का भविष्य तबाह हो जाएगा।

ब्रीफ न्यूज

एसजेवीएन 700 करोड़ रुपये से लगाएगी 100 मेगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजना

नई दिल्ली। बयान के मुताबिक, एसजेवीएन ने ई-रिवर्स नीलामी के जरिये निर्माण, स्वामित्व और संचालन के आधार पर 2.90 रुपये प्रति यूनिट की दर पर 100 मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना की क्षमता स्थापित करने का मौका हासिल किया है। इस परियोजना के विकास पर 700 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एसजेवीएन ने शुक्रवार को 700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 100 मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की घोषणा की। एसजेवीएन ने एक बयान में कहा कि उसने भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) से ई-रिवर्स नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से यह परियोजना हासिल की है। बयान के मुताबिक, एसजेवीएन ने ई-रिवर्स नीलामी के जरिये निर्माण, स्वामित्व और संचालन के आधार पर 2.90 रुपये प्रति यूनिट की दर पर 100 मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना की क्षमता स्थापित करने का मौका हासिल किया है। इस परियोजना के विकास पर 700 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। एसजेवीएन ने कहा कि इस परियोजना को उसकी पूर्ण-स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी एसजीईएल के जरिये देश में कहीं भी विकसित किया जाएगा। परियोजना के संचालन के पहले वर्ष में 26.2 करोड़ यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने का अनुमान है और 25 साल की अवधि में इसका कुल ऊर्जा उत्पादन लगभग 657.4 करोड़ यूनिट होगा। एसजेवीएन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा ने कहा कि यह परियोजना एसईसीआई के साथ बिजली बिक्री समझौते (पीएसए) पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 24 महीने की अवधि में चालू हो जाएगी।

गूगल ने एंड्रॉयड पर प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले को एनसीएलएटी में दी चुनौती

नई दिल्ली। गूगल के प्रवक्ता ने पीटीआई-से कहा, ''हमने एंड्रॉयड पर सीसीआई के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है। हमारा मानना है कि यह फैसला उन भारतीय प्रयोगकर्ताओं, कंपनियों के लिए बड़ा झटका है जिन्हें एंड्रॉयड की सुरक्षा खूबियों पर भरोसा है। इससे मोबाइल उपकरणों की लागत संभावित रूप से बढ़ जाएगी।'' दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में अनुचित व्यापार व्यवहार के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील की है। कंपनी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गूगल के प्रवक्ता ने पीटीआई-से कहा, ''हमने एंड्रॉयड पर सीसीआई के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है। हमारा मानना है कि यह फैसला उन भारतीय प्रयोगकर्ताओं, कंपनियों के लिए बड़ा झटका है जिन्हें एंड्रॉयड की सुरक्षा खूबियों पर भरोसा है। इससे मोबाइल उपकरणों की लागत संभावित रूप से बढ़ जाएगी।'' प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने फैसले में एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का फायदा उठाने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही सीसीआई ने इंटरनेट क्षेत्र की कंपनी को कई तरह के अनुचित व्यापार व्यवहार से बचने को कहा था। इस पर गूगल के प्रवक्ता ने कहा, हम एनसीएलएटी में अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही हम अपने प्रयोगकर्ताओं तथा भागीदारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंपनी ने कहा कि एंड्रॉयड ने भारतीय प्रयोगकर्ताओं, डेवलपर्स और ओईएम को लाभ दिया है और इसने देश के डिजिटल बदलाव को आगे बढ़ाया है। सूत्रों ने कहा कि गूगल ने एनसीएलएटी से आयोग के आदेश पर रोक लगाने की अपील की है। गूगल का मानना है कि सीसीआई इस बात पर गौर करने में विफल रहा कि मुक्त एंड्रॉयड कारोबारी मॉडल सभी अंशधारकों के लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा का समर्थन करता है, खासकर भारत के मामले में। सूत्रों के मुताबिक, गूगल को भरोसा है कि एनसीएलएटी इस मामले में मौजूद प्रमाणों पर गौर करेगा कि एंड्रॉयड ने भारत में मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र की भारी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से प्रभावित हो सकता है देश का निर्यात

एनटीवी न्यूज

नई दिल्ली। राजनीतिक स्थिरता, माल की आवाजाही, कंटेनरों और शिपिंग लाइनों की पर्याप्त उपलब्धता, मांग, स्थिर मुद्रा और सुचारू बैंकिंग प्रणाली जैसे सभी वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाले कारक अब बिखर रहे हैं। संकट को बढ़ाते हुए, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों में कोविड महामारी के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं।

भारत का निर्यात भले ही वित्त वर्ष 2021-22 में 422 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर को छू गया हो, लेकिन प्रमुख पश्चिमी बाजारों में 'मंदी' और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भू-राजनीतिक संकट की छाया अगले साल यानी 2023 में देश के निर्यात को प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक स्थिरता, माल की आवाजाही, कंटेनरों और शिपिंग लाइनों की पर्याप्त उपलब्धता, मांग, स्थिर मुद्रा और सुचारू बैंकिंग प्रणाली जैसे सभी वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाले कारक अब बिखर रहे हैं। संकट को बढ़ाते हुए, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों में कोविड महामारी के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं।

इससे पहले कि कोविड-प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट से बाहर आ पाती, फरवरी में रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रकोप ने दुनियाभर में आपूर्ति श्रृंखला को गंभीर रूप से बाधित कर दिया और वैश्विक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया। युद्ध ने महत्वपूर्ण काला सागर मार्ग से माल की आवाजाही को भी प्रभावित किया। बिगड़ती भू-राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार में केवल एक प्रतिशत की वृद्धि होगी। जिनेवा स्थित बहुपक्षीय व्यापार निकाय ने कहा है कि विश्व व्यापार में वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में गति कम होने और वर्ष 2023 में कमजोर रहने की उम्मीद है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कई झटके लगे हैं।

इसने कहा, "डब्ल्यूटीओ के अर्थशास्त्री अब भविष्यवाणी करते हैं कि वर्ष 2022 में वैश्विक व्यापारिक व्यापार की मात्रा 3.5 प्रतिशत बढ़ेगी – जो अप्रैल में तीन प्रतिशत पूर्वानुमान से थोड़ा बेहतर है। हालांकि, वर्ष 2023 के लिए वे एक प्रतिशत की ही वृद्धि होने की उम्मीद व्यक्त करते हैं – जो 3.4 प्रतिशत के पिछले अनुमान से काफी कम है।'' जानकारों के मुताबिक, इन घटनाक्रमों के बीच भारत के लिए खुद को इन काली घटाओं से बचाना मुश्किल होगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत ने अबतक वस्तुओं निर्यात में वृद्धि हासिल की है और सेवाओं के निर्यात में भी अच्छी वृद्धि से भी 2023 में देश से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र का निर्यात भी 254 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर को छू गया और उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, यह इस वित्त वर्ष में 300 अरब डॉलर के स्तर को छू सकता है। इस साल जुलाई, अगस्त और सितंबर में निर्यात क्रमशः 2.14 प्रतिशत, 1.62 प्रतिशत और 4.82 प्रतिशत बढ़ा। अक्टूबर में इसमें 12.12 प्रतिशत की कमी आई और नवंबर में निर्यात वृद्धि सपाट रही। अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान निर्यात 11 प्रतिशत बढ़कर 295.26 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 265.77 अरब डॉलर था।

हालांकि, चालू वित्त वर्ष के पहले आठ माह की अवधि के दौरान आयात 29.5 प्रतिशत बढ़कर 493.61 अरब डॉलर का हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान यह 381.17 अरब डॉलर था। मंत्रालय के अनुसार, व्यापारिक निर्यात में गिरावट के कारणों में कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कोविड महामारी का प्रसार और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण मंदी और उसके परिणामस्वरूप मांग में आई गिरावट तथा घरेलू मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किये गये कुछ उपाय शामिल हैं।

भारत के लिए बड़ी समस्या व्यापार घाटे (आयात और निर्यात के बीच का अंतर) का बढ़ना होगा, जिसका रुपये के मूल्य और चालू खाते के घाटे (कैड) पर असर पड़ता है। डेलॉयट इंडिया के अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि वैश्विक व्यापार की स्थिति को देखते हुए भारत के निर्यात में कमी आने की आशंका है। हालांकि, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट आंशिक रूप से इस प्रभाव को कम कर सकती है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार में एक प्रतिशत की गिरावट का भारतीय निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सहाय ने कहा, ''हालांकि, हम इस तथ्य को भी जानते हैं कि वैश्विक व्यापार में हमारा हिस्सा अब भी दो प्रतिशत से कम है। इसलिए वैश्विक व्यापार की घट-बढ़ का हमपर अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा कुछ सकारात्मक घटनाक्रम भी वर्ष 2023 में भारत के लिए मददगार साबित होंगे।

उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में हुआ मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी उपयोग से आने वाले महीनों में निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और कनाडा के साथ नए समझौते भी वर्ष 2023 की पहली छमाही में निर्यात को और बढ़ावा दे सकता हैं। उन्होंने कहा कि रुपये के मूल्य में आई गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है क्योंकि निर्यात के मुकाबले हमारा आयात कहीं 50 प्रतिशत अधिक है। रुपये में थोड़ी घट-बढ़ निर्यातकों के लिए बेहतर है लेकिन भारी घट-बढ़ के कारण जोखिम हो सकता है। मुंबई स्थित निर्यातक और टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शारदा कुमार सर्राफ ने कहा कि हालांकि यूरोप, अमेरिका और जापान जैसी सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के संकेत दिख रहे हैं, फिर भी भारतीय निर्यात में वर्ष 2023 में 8-10 प्रतिशत की वृद्धिकी संभावना है।

सरकार आज बताएगी अर्थव्यवस्था का हाल, अभी क्या है दिग्गजों का अनुमान और वास्तविक स्थिति

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े जारी करेगा. इन आंकड़ों का उपयोग आगामी बजट तैयार करने के लिए किया जाएगा. हालांकि, इसी बीच केंद्रीय बैंक आरबीआई ने देश की जीडीपी के ग्रोथ अनुमान को 0.2 फीसदी कम कर दिया है.

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय शुक्रवार शाम को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का पहला अनुमान जारी करेगा. यह आंकड़े तब जारी किए जा रहे हैं जब इसके तीन हफ्ते बाद 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश होने वाला है. बता दें कि इस डेटा का उपयोग सरकार अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट को तैयार करने के लिए करेगी. इस लिहाज़ से ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हैं. आरबीआई ने 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था. इसने दिसंबर 2022 में तीसरी बार 2022-23 के लिए विकास अनुमान को पार कर लिया था.

आरबीआई ने घटाया इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान

पिछले महीने की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 7 प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया था. इसके पीछे की वजह विश्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय संकट को बताया गया था.

केंद्रीय बैंक ने पहले भी घटाया अनुमान

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि पिछली तिमाही में 13.5 प्रतिशत से घटकर 6.3 प्रतिशत हो गई. हालांकि, अप्रैल 2022 में केंद्रीय बैंक ने जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 7.8 प्रतिशत से घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया था और पिछले साल सितंबर में इसे घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया था.

विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक को अच्छी ग्रोथ की उम्मीद

विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को अपने पहले के 6.5 प्रतिशत के अनुमान से बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है. वहीं एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 7 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा है. जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने जुलाई 2022 में अनुमानित 7.4 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया था.

वित्त मंत्रालय ने बैंकों से बीमा पॉलिसियां बेचने के लिए अनैतिक तरीकों से बचने को कहा

नई दिल्ली। *सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों को लिखे पत्र में कहा गया है कि वित्तीय सेवा विभाग को शिकायतें मिली हैं कि बैंक और जीवन बीमा कंपनियों द्वारा बैंक ग्राहकों को पॉलिसी की बिक्री के लिए धोखाधड़ी वाले और अनैतिक तरीके अपनाए जा रहे हैं।*

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए 'अनैतिक व्यवहार' पर रोक लगाने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए सही जानकारी नहीं दी जाती है। इसके मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों को लिखे पत्र में कहा गया है कि वित्तीय सेवा विभाग को शिकायतें मिली हैं कि बैंक और जीवन बीमा कंपनियों द्वारा बैंक ग्राहकों को पॉलिसी की बिक्री के लिए धोखाधड़ी वाले और अनैतिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं, जहां दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में 75 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहकों को जीवन बीमा पॉलिसी बेची गई है। आमतौर पर, बैंकों की शाखाएं अपनी अनुषंगी बीमा कंपनियों के उत्पादों का प्रचार-प्रसार करती हैं।

जब ग्राहकों द्वारा पॉलिसी लेने से इनकार किया जाता है, तो शाखा अधिकारी बड़ी शिद्दत से समझाते कि उनपर ऊपर से दबाव है। जब ग्राहक किसी प्रकार का ऋण लेने या सावधि जमा खरीदने जाते हैं, तो उन्हें बीमा उत्पाद लेने को कहा जाता है। इस संबंध में विभाग ने पहले ही एक परिपत्र जारी किया है जिसमें यह सलाह दी गई है कि किसी बैंक को किसी विशेष कंपनी से बीमा लेने के लिए ग्राहकों को मजबूर नहीं करना चाहिए। यह भी बताया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने आपत्ति जताई है कि बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए प्रोत्साहन से न केवल फील्ड कर्मचारियों पर दबाव पड़ता है बल्कि बैंकों का मूल कारोबार भी प्रभावित होता है। ऐसे में कर्मचारियों को कमीशन और प्रोत्साहन के लालच की वजह से कर्ज की गुणवत्ता से 'समझौता' हो सकता है।

कैट की ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण बनाने की मांग

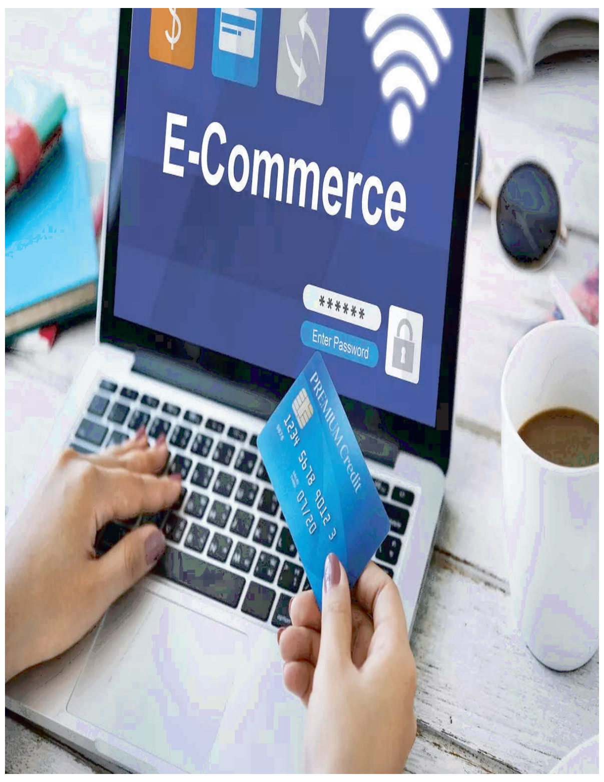

नई दिल्ली। इसके अलावा समिति ने भारी छूट, स्वयं तरजीह देने और खोज एवं रैंकिंग में प्राथमिकता देने जैसे व्यवहार से दूर रहने के लिए कहा है, जो बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं। व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को तुरंत एक मजबूत ई-कॉमर्स नीति लागू करनी चाहिए और इस खंड के लिए एक नियामक प्राधिकरण का गठन करना चाहिए। कैट ने अपनी मांगें ऐसे समय रखी हैं जबकि एक दिन पहले ही एक संसदीय समिति ने डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार को रोकने के लिए पूर्वानुमानित नियमन, महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यस्थ को श्रेणीबद्ध करने और एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून लाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा समिति ने भारी छूट, स्वयं तरजीह देने और खोज एवं रैंकिंग में प्राथमिकता देने जैसे व्यवहार से दूर रहने के लिए कहा है, जो बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं। कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने पीटीआई-से कहा कि सेबी और आरबीआई की तरह एक नियामक प्राधिकरण होना चाहिए, जो भारत में ई-कॉमर्स कारोबार को विनियमित कर सके। खंडेलवाल ने कहा, ''सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स नियम जारी करने चाहिए, एफडीआई खुदरा नीति के 2018 के प्रेस नोट दो के स्थान पर एक नया प्रेस नोट जारी करना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि अगर ई-कॉमर्स के लिए भारत में नए नियम लागू नहीं किए गए, तो विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां देश के करोड़ों छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएंगी।

बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 453 अंक टूटा, 17,900 के नीचे बंद

नई दिल्ली. भारतीय शेयर बाजार (Share Market) में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई. बाजार में मुनाफावसूली का दबाव हावी रहा. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिली. वहीं आईटी, बैंकिंग, मेटल और फार्मा शेयरों में गिरावट नजर आई. बाजार में रियल्टी, पीएसई और ऑटो शेयरों पर दबाव देखने को मिला. कारोबार के अंत में सेंसेक्स (Sensex) 452.90 अंक यानी 0.75 फीसदी गिरकर 59,900 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी (Nifty) 132.70 अंक यानी 0.74 फीसदी टूटकर 17,859.50 पर बंद हुआ.

पिछले कारोबारी सत्र में, गुरुवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 304 अंक गिरकर 60,353 पर बंद हुआ था. इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 51 अंक टूटकर 17,992 पर बंद हुआ था. नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी एनएसओ (NSO) 2022-23 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का पहला अग्रिम आकलन शुक्रवार शाम को जारी करेगा. इसके तीन हफ्ते बाद, एक फरवरी को लोकसभा में बजट पेश होगा. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इन आंकड़ों का उपयोग अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के बजट को तैयार करने के लिए किया जाता है.

पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार 8 साल के लो पर पहुंचा

पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार आठ वर्ष के निचले स्तर 5.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे देश के सामने चूक का जोखिम भी बढ़ गया है. अर्थव्यवस्था को संभालने के सरकार के प्रयासों के बावजूद देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है. डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) का विदेशी मुद्रा भंडार 30 दिसंबर 2022 को खत्म हुए हफ्ते के दौरान घटकर 5.576 अरब डॉलर रह गया जो इसका 8 साल का निचला स्तर है.

ग्राहक को KYC अपडेट करवाने के लिए बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं: RBI

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक के खाताधारकों ने अगर अपने वैध दस्तावेज जमा करवा दिए हैं और उनके पते में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो 'अपने ग्राहक को जानें (KYC)' विवरण को अपडेट करवाने के लिए उन्हें बैंक ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं है. इसमें कहा गया कि यदि केवाईसी विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो खाताधारक अपनी ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एटीएम या किसी भी अन्य डिजिटल माध्यम के जरिए स्व-घोषणा पत्र जमा करवा सकते हैं.

मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 200 से अधिक नौकरशाह हुए शामिल

एनटीवी न्यूज

तीन दिवसीय सम्मेलन कल से शुरू हुआ। इस सम्मेलन के पीछे विचार यह है कि केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के साथ मिलकर काम करने वाले विभागों के माध्यम से सहकारी संघवाद नए भारत के विकास और प्रगति के लिए एक आवश्यक स्तंभ है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, पीएम मोदी ने इस सम्मेलन की परिकल्पना की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में राज्यों के साथ साझेदारी में तेजी से और निरंतर आर्थिक विकास हासिल करने पर केंद्रित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। तीन दिवसीय सम्मेलन कल से शुरू हुआ। इस सम्मेलन के पीछे विचार यह है कि केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के साथ मिलकर काम करने वाले विभागों के माध्यम से सहकारी संघवाद नए भारत के विकास और प्रगति के लिए एक आवश्यक स्तंभ है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, पीएम मोदी ने इस सम्मेलन की परिकल्पना की, जो पहली बार जून 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था। इस वर्ष, मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 5 जनवरी से आयोजित किया जा रहा है और 7 जनवरी को समाप्त होगा। 200 से अधिक नौकरशाहों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और डोमेन विशेषज्ञ शामिल हैं। सम्मेलन में भाग लेते हुए, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बयान में कहा गया है। यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है जब पीएम मोदी ने भारत की कई जटिल चुनौतियों का जवाब देने के लिए दक्षता और तालमेल लाने के लिए सहकारी संघवाद का लाभ उठाने की कोशिश की है। पिछले 8 वर्षों में, पीएम मोदी ने नीति-निर्माण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को अधिक सहयोगात्मक और परामर्शात्मक बनाने के लिए काम किया है, इस प्रकार भारत को अधिक संघ शासित बनाया है। बयान में कई अवसरों की सूची है जहां पीएम मोदी ने भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करने और केंद्र-राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं। पीएम मोदी द्वारा जनवरी 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पिछड़े जिलों के परिवर्तन में तेजी लाने के उद्देश्य से की गई थी। सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से देश।

मणिपुर को अमित शाह ने दी परियोजनाओं की सौगात, कहा- हमने आतंकवाद से मुक्त क्षेत्र का किया था वादा

अमित शाह ने कहा कि मैं हमारे बीरेन सिंह जी को धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि जो घर अंग्रेजों के गोलाबारी में टूट गया था उसको बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत बड़ा शहीद स्मारक बनाया। मोइरांग में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने वादा किया था कि मणिपुर को आतंकवाद से मुक्त कराएंगे, आज मणिपुर पूर्णतया आतंकवाद से मुक्त होकर मोदी जी और बीरेन सिंह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर चल रहा है। मैं हमारे बीरेन सिंह जी को धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि जो घर अंग्रेजों के गोलाबारी में टूट गया था उसको बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत बड़ा शहीद स्मारक बनाया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोइरांग में आईएनए मुख्यालय में 175 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं चुराचंदपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर में एक हजार तीन सौ 11 करोड़ रुपये की 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधाशिला रखी।

इंटर स्टेट बाउंड्री समझौते पर रोकः असम, मेघालय ने किया शीर्ष अदालत का रुख

एनटीवी न्यूज

नयी दिल्ली। सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर दोनों राज्यों के बीच हुए अंतरराज्यीय समझौते पर असम, मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से दाखिल किए गए प्रतिवेदन पर गौर किया। असम और मेघालय की सरकारों ने अपने सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर दोनों राज्यों के बीच हुए अंतरराज्यीय समझौते के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर दोनों राज्यों के बीच हुए अंतरराज्यीय समझौते पर असम, मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से दाखिल किए गए प्रतिवेदन पर गौर किया। इसमें कहा गया था कि मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय की एकल और खंडपीठ ने उस अंतर-राज्यीय सीमा समझौते के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है जिस पर पिछले साल हस्ताक्षर किए गए थे। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''हम इस पर सुनवाई करेंगे। कृपया याचिका की तीन प्रतियां सौंपें।''
मेघालय उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतरराज्यीय सीमा समझौते के तहत जमीन पर भौतिक सीमांकन या सीमा चौकियों के निर्माण पर गत वर्ष नौ दिसंबर को अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था जिस कारण दोनों राज्यों ने शीर्ष अदालत का रुख किया।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा और असम के उनके समकक्ष हिमंत विश्व शर्मा ने दोनों राज्यों के बीच अक्सर तनाव उत्पन्न करने वाले 12 विवादित क्षेत्रों में से कम से कम छह के सीमांकन के लिए पिछले साल 29 मार्च में एक समझौता ज्ञापन पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद 50 साल पुराना है। हालांकि, हाल के दिनों में इसे हल करने के प्रयासों में तेजी लाई गई है। दोनों राज्यों की सीमा करीब 884.9 किमी लंबी है। असम से अलग करके 1972 में मेघालय का गठन किया गया था, लेकिन नए राज्य ने असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 को चुनौती दी जिसके बाद 12 सीमावर्ती स्थानों को लेकर विवाद शुरू हुआ।

इनसाइड

इंडियन ऑसियन में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच बड़े संदेश दे गया रक्षामंत्री का अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का दौरा

रक्षा मंत्री ने अंडमान दौरे के दौरान क्वाड-सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर की समीक्षा की और 29 दिसंबर, 1943 को नेताजी के ऐतिहासिक आगमन के स्थान संकल्प स्मारक का दौरा किया। साथ ही उन्होंने भारतीय सुरक्षा बलों की परिचलानगत क्षमताओं की समीक्षा भी की। चीन की संभावित चालों से निपटने की तैयारी में जुटा भारत लगातार अपनी सीमाओं को तो सुरक्षित बना ही रहा है साथ ही सैन्य बलों की परिचालन क्षमताओं की भी समीक्षा कर रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और खासकर चीन के साथ तनाव वाली सीमाओं पर नजर रखे हुए हैं। अभी हाल ही में वह अरुणाचल प्रदेश के अहम दौरे पर गये थे उसके बाद वह अंडमान निकोबार पहुँचे।
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में देश की एकमात्र एकीकृत सैन्य कमान की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा करने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य अपनी सेना को दुनिया की सबसे मजबूत सेना बनाना है। हम आपको बता दें कि अंडमान-निकोबार कमान (एएनसी) हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ के मद्देनजर इस क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
अंडमान-निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने रक्षा मंत्री को द्वीपसमूह की भू-रणनीतिक क्षमता और भारत के प्रभाव को बढ़ाने व क्षेत्र में सैन्य अभियानों के समर्थन में द्वीपों की भूमिका के बारे में बताया।
रक्षा मंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में कमान के मुख्यालय की यात्रा के दौरान द्वीपसमूह के सामरिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का भी जायजा लिया। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने और समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए कमान की सराहना करते हुए कहा, "हमारा उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक बनाना है।" रक्षा मंत्री ने उस बहादुरी और मुस्तैदी का भी विशेष उल्लेख किया, जिसके साथ सशस्त्र बल उत्तरी क्षेत्र में हाल की स्थितियों से निपटे।

समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग, SC ने हाईकोर्ट में लंबित याचिकाएं ट्रांसफर करने के दिए निर्देश, 13 मार्च को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख तय की है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

एलजीबीटीक्यू अधिकारों के लिए बड़ा कदम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे पर सुनवाई को तैयार नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।

सरकार 15 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख तय की है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आदेश लिखवाते हुए कहा कि चूंकि एक ही विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई याचिकाएं लंबित हैं, हम सभी याचिकाओं को इस न्यायालय के समक्ष स्थानांतरित करने का निर्देश देते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को आभासी मंच पर उपस्थित होने और अपनी प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान की है। जो भी इसके लिए पूछेगा उसे लिंक प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों को नोटिस जारी किया जाएगा। जवाबी हलफनामा 15 फरवरी 2023 तक दायर किया जाना है।

रूस हो या यूक्रेन भारत को लेकर क्यों आलोचनात्मक नहीं होते? पर्दे के पीछे की इस कहानी को आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान

एनटीवी संवाददाता

संयुक्त राष्ट्र से लेकर वैश्विक मंचों पर रूस-यूक्रेन जंग को लेकर भारत के कमद की जहां एक तरफ पश्चिमी देशों की तरफ से तीखी आलोचना की जा रही थी। उस वक्त भी यूक्रेन भारत के प्रति मुखर नहीं हुआ।

एक गुरु बनने के लिए क्या आवश्यक है इसकी व्याख्या भारत को इस बात की अभिलाषा देने वाले स्वामी विवेकानंद ने स्वयं की थी। अपने निबंध 'माई मास्टर' (1901) में उन्होंने लिखा: ''अगर आप सच्चे सुधारक बनना चाहते हैं तो तीन चीजें आवश्यक हैं। पहली है महसूस करना। क्या आप सचमुच अपने भाइयों की पीड़ा अनुभव करते हैं?' क्या आप सहानुभूति से ओत-प्रोत हैं?' क्या आपने बिना किसी अशुद्धि उस सोने को सहेजने के तरीके खोज लिए हैं? अगर आपने ऐसा कर लिया है, एक और चीज आवश्यक है। आपका इरादा क्या है? क्या आपको विश्वास है कि आप लालच, प्रसिद्धि या शक्ति की पिपासा से प्रेरित नहीं हैं?'तब आप एक सच्चे सुधारक हैं, आप मानवता के लिए एक शिक्षक, एक गुरु, एक आशीष हैं।'' ऐसे में नरेंद्र मोदी के रूप में दुनिया को एक ग्लोबल लीडर मिला है जिसने वक्त पड़ने पर अन्य देशों के लिए सहयोग का हाथ भी बढ़ाया है। तभी तो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया महान तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा संजीवनी लाने वाला हनुमान। रूस-यूक्रेन युद्ध और भारत की चौखट पर चीन की आक्रामकता ने वैश्विक भू-राजनीति में उथल-पुथल मचाई और अब भारत कूटनीतिक और सैन्य मोर्चों पर चुनौतियों और अवसरों के साथ 2023 में प्रवेश कर रहा है।

बीता पूरा साल जब जंग के साए में गुजरा तो उस वक्त भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी ने शांति का संदेश देते हुए दो टूक कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र से लेकर वैश्विक मंचों पर रूस-यूक्रेन जंग को लेकर भारत के कमद की जहां एक तरफ पश्चिमी देशों की तरफ से तीखी आलोचना की जा रही थी। उस वक्त भी यूक्रेन भारत के प्रति मुखर नहीं हुआ। वो तो बस विश्व गुरु के प्रति इस भाव से टकटकी लगाए देखता रहा कि युद्ध को बस भारत ही रुकवा सकता है। जहां एक तरफ रूस-यूक्रेन जंग के बीच दुनिया दो खेमे में बंट गई है। वहीं भारत ही एक ऐसा देश है जिससे रूसी राष्ट्रपति भी बात करते हैं वहीं यूक्रेन के जेलेंस्की भी। सबसे पहले अगर बात यूक्रेन की करें तो उसने भारत के खिलाफ एक भी बात नहीं कहा। जहां एक तरफ युद्ध की शुरुआत के साथ ही तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन के समर्थन का दिखावा करते दिखे। वहीं भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक तरीके से विवाद का हल निकालने की अपील करता नजर आया। कई देशों ने रूस के कदम का सीधा विरोध किया लेकिन भारत की तरफ से रूस की आलोचना नहीं की गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत युद्ध के पक्ष में नजर आया। बल्कि अगर अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के चीफ बिल बनर्स की माने तो ये पीएम मोदी ही थे जिनकी वजह से परमाणु युद्ध टल गया। सीआईए चीफ ने कहा भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का रूस के फैसलों पर असर रहा है। बर्न्स के अनुसार, पीएम मोदी ने बार-बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई। तो जरा सोचिये, अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया में कैसा तबाही का मंजर नजर आता। इतना ही नहीं जंग की वजह से दुनिया पर छाए भुखमरी के संकट को टालने में भी भारत ने पर्दे के पीछे रहते हुए अहम भूमिका निभाई। बता दें कि अनाज संकट की वजह से रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ था। जिसमें काले सागर के रास्ते लाखों टन अनाज पोत के माध्यम से यूक्रेन से बाहर भेजने की अनुमति दी गई थी। भारत ने इस समझौते का समर्थन भी किया था। लेकिन बाद में रूस इससे पीछे हटने लगा। बाद में भारत ने रूस को फिर से इस समझौते को कायम रखने में अहम भूमिका निभाई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अपने ऑस्ट्रिया दौरे के दौरान इसका जिक्र करते हुए बताया था कि भारत ने कीव और मॉस्को के बीच के अनाज सौदे पर गुपचुप तौर पर मदद की थी। जियो पॉलिटिक्स के लिहाजे से देखा जाए तो भारत का इस मसले से सीधा कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि पहली बार ये कोई बड़ा युद्ध नहीं है। मसलन, भारत से इतर इसकी धुरी यूक्रेन रूस, नाटो, अमेरिका के ही ईर्द-गिर्द घूम रही है। ये और बात है कि अमेरिका वाशिंगटन से भारत पर दोनों देशों की दोस्ती की दुहाई देकर इस बात का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसका साथ दे। भारत ने 2014 में भी किसी का पक्ष नहीं लिया था, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा जमा लिया था। यही नहीं यूक्रेन की संप्रभुता को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से भी भारत ने दूरी बना ली थी। भारत पॉलिसी ही यही है कि वह युद्ध की नीति पर नहीं चलता है। पीएम मोदी ने भी रूसी राष्ट्रपति को दो टूक कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है। रूस-यूक्रेन जंग के बाद पश्चिमी देशों के निशाने पर मॉस्को आ गया और उस पर प्रतिबंधों की बारिश हो गई। लेकिन इससे इतरर भारत रूस के साथ अपने संबंधों और अपने हितों को ध्यान में रखकर रूस से कच्चा तेल समते तमाम चीजें खरीदता रहा।

जेपी नड्डा ने चित्रदुर्ग में कार्यकर्ता समावेश को किया संबोधित, कहा- यूपीए जैसी पिछली सरकारें वंशवादी पार्टियां थीं

पीएम मोदी के नेतृत्व में, 'वैक्सीन मैत्री' कार्यक्रम के माध्यम से, भारत ने 100 से अधिक देशों को COVID वैक्सीन की आपूर्ति की, जिसमें 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन प्राप्त हुई।

जेपी नड्डा ने कहा कि यूपीए जैसी पिछली सरकारें वंशवादी पार्टियां थीं। वे वोट बैंक की राजनीति में विश्वास करके सरकार चला रहे थे। वे बांटो और राज करो की बुनियाद पर अमल कर रहे थे और देश को जातियों और धर्म के आधार पर बांट रहे थे।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में पेशेवरों के साथ बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसा कि कर्नाटक में चुनाव नजदीक हैं, यहां के लोगों से बातचीत करना और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करना मेरी प्रमुख जिम्मेदारी बन जाती है। जब पीएम मोदी ने 2014 में पदभार संभाला था, तो यह सिर्फ प्रधानमंत्री का, पार्टी का, सरकार का बदलाव नहीं था, यह वास्तव में देश में राजनीतिक संस्कृति का बदलाव था।
जेपी नड्डा ने कहा कि यूपीए जैसी पिछली सरकारें वंशवादी पार्टियां थीं। वे वोट बैंक की राजनीति में विश्वास करके सरकार चला रहे थे। वे बांटो और राज करो की बुनियाद पर अमल कर रहे थे और देश को जातियों और धर्म के आधार पर बांट रहे थे। दुनिया पर मंडरा रहे घोर संकट के समय में न तो अमेरिका और न ही ब्रिटेन मानवता को बचाने या अर्थव्यवस्था को बचाने के बीच फैसला कर सका, और यह भारत ही था, जिसने लॉकडाउन की घोषणा करने और कोरोना की उस बड़ी चुनौती को अच्छी तरह से प्रबंधित करने का समयबद्ध और साहसिक निर्णय लिया।
जेपी नड्डा ने कहा कि एक वैक्सीन विकसित होने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन कोविड के चुनौतीपूर्ण समय में, यह अप्रैल 2020 था, जब मोदी जी ने एक टास्क-फोर्स का गठन किया, पर्याप्त धन मुहैया कराया, और कम समय में रिकॉर्ड-कम समय में कोविड वैक्सीन विकसित करने में मदद की। पीएम मोदी के नेतृत्व में, 'वैक्सीन मैत्री' कार्यक्रम के माध्यम से, भारत ने 100 से अधिक देशों को COVID वैक्सीन की आपूर्ति की, जिसमें 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन प्राप्त हुई।
हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके हैं। यह वह देश था जिसने दो शताब्दियों तक हम पर शासन किया और अब वह समय है जब हम इससे बहुत आगे खड़े हैं। यह सब पीएम मोदी जी के मजबूत दूरदर्शी नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में महान उपलब्धियां हासिल करने से लेकर इस्पात निर्माण में उच्च प्रगति करने तक, भारत सभी क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ रहा है।

कानपुर में भीषण शीतलहर हुई जानलेवा, 25 लोगों की हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के कारण मौत

कानपुर: उत्तर प्रदेश में शीतलहर दिन पर दिन जानलेवा होती जा रही है। कानपुर में गुरुवार को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 25 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 17 लोगों की चिकित्सा सहायता मिलने से पहले ही मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक ठंड में ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ जाना और खून का थक्का जमना हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक का कारण बन रहा है। कार्डियोलॉजी संस्थान के कंट्रोल रूम के अनुसार गुरुवार को इमरजेंसी व ओपीडी में 723 हृदय रोगी आए। इनमें से 41 मरीज जिनकी हालत गंभीर थी, उन्हें भर्ती किया गया। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज करा रहे सात हृदय रोगियों की ठंड के कारण मौत हो गई। इसके अलावा 15 मरीजों को मृत अवस्था में इमरजेंसी में लाया गया। कार्डियोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर विनय कृष्ण ने कहा कि इस मौसम में मरीजों को ठंड से बचाना चाहिए। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के एक फैकल्टी सदस्य ने कहा, ₹इस ठंड के मौसम में दिल का दौरा केवल बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं है। हमारे पास ऐसे मामले हैं जब किशोरों को भी दिल का दौरा पड़ा है। हर कोई, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, गर्म रहना चाहिए और जितना हो सके घर के अंदर ही रहना चाहिए। दिल्ली में शुक्रवार को दूसरे दिन भी शीत लहर का प्रकोप जारी रहा और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान गिरकर 1.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत और देश के मध्य तथा पूर्वी हिस्सों में कोहरे की घनी चादर छाई रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ।